RNI No. 58061/93 ▪ वर्ष - 21 ▪ अंक - 132 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » शनिवार » 06-12-2025 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 केकेआर के लिए 'एक्स फैक्टर' हो सकते हैं उमरान : सुनील नारायण
6 संचार साथी ऐप : अपेक्षा है निजता बनाम सुरक्षा के बीच संतुलन की
7 काशिका कपूर ने बिखेरी ओल्ड-हॉलीवुड ग्लैमर की चमक

फर्स्ट टेक

क्लाउडफ्लेयर ने नेटवर्क में आई खराबी के जांच के आदेश दिए, कई साइट ठप

मैड्रिड/एपी। इंटरनेट अवसंरचना कंपनी 'क्लाउडफ्लेयर' ने शुक्रवार को कहा कि वह सुबह आई तकनीकी खामी की जांच कर रही है, जिसके कारण लिंक्डइन, जूम और अन्य सहित कई वैश्विक वेबसाइटें ठप हो गई थीं। क्लाउडफ्लेयर द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं में गत तीन सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार खामी आई है। क्लाउडफ्लेयर ने दावा किया कि समस्या का समाधान हो गया है और वह ''क्लाउडफ्लेयर डैशबोर्ड और संबंधित एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई)'' के साथ समस्याओं की जांच कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर प्रणाली को एक दूसरे के साथ समन्वय करने में सक्षम बनाते हैं। इस बीच, सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर उपयोगकर्ताओं ने वेबसाइट इस्तेमाल करने में आने वाली समस्याओं की सूचना दी।

भारतीय सेना ने पर्वत चोटी कांग्टो को फतह किया

ईटानगर/भाषा। भारतीय सेना की पूर्वी कमान की एक टीम अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कांग्टो को फतह करने वाली पहली टीम बन गई है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि माउंट कांग्टो की ऊंचाई 7,042 मीटर है और यह देश के पर्वतारोहण इतिहास में एक मील का पत्थर है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल श्रीधरन ने एक बयान में बताया कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण दक्षिणी मार्ग से होते हुए टीम ने अब तक अजेय रही चोटी को सफलतापूर्वक फतह किया। उन्होंने बताया कि इस चोटी को लंबे समय से कामेंग हिमालय का अभेद्य प्रहरी माना जाता है।

ईरान ने होर्मुज खाड़ी में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी

तेहरान/एपी। ईरान की नौसेना ने अपने युद्धाभ्यास के दूसरे दिन ओमान सागर और रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य के पास बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागीं। सरकारी टेलीविजन चैनल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकारी टीवी चैनल ने खबर दी कि अर्धसैनिक बल 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने बृहस्पतिवार को शुरू हुए युद्धाभ्यास के तहत ईरान की मुख्य भूमि के भीतरी हिस्सों से मिसाइलें दागीं और ओमान सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट पड़ोसी क्षेत्र में तय लक्ष्यों पर निशाना साधा। खबर के मुताबिक अभ्यास के दौरान कद्र-110, कद्र-380 और गदीर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया जिनकी मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर (1,250 मील) तक है।

सूर्यास्त 06-12-2025 5:52 बजे	सूर्योदय 07-12-2025 6:29 बजे
BSE 85,712.37 (+447.05)	NSE 26,186.45 (+152.70)
सोना 13,373 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 181,385 रु. प्रति किलो

मोदी और पुतिन ने आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर चर्चा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत और रूस ने शुक्रवार को आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी गुप्त एजेंडे और दोहरे मापदंड के बिना किसी समझौते के वैश्विक लड़ाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह खतरा मानवता के मूल्यों पर सीधा हमला है।

प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय शिखर वार्ता में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की और आतंकवाद के प्रति ' कतई बर्दाश्त नहीं' की नीति पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने आतंकवादियों की सीमापार से घुसपैठ और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित सभी प्रकार के आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मोदी ने कहा, ''भारत और रूस लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। चाहे वह पहलगाम में आतंकवादी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर कायरतापूर्ण हमला - इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है।'' उन्होंने कहा, ''भारत का दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा हमला है और इसके खिलाफ वैश्विक एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।''

दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि मोदी और पुतिन ने आतंकवाद के सभी कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा की, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो।

मोदी ने पुतिन को असम की काली चाय, कश्मीरी केसर और भगवद गीता उपहार में दिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार स्वरूप असम की स्वादिष्ट काली चाय, कश्मीरी केसर, हस्तनिर्मित घोड़े की चांदी की प्रतिकृति, एक सजावटी टी सेट और भगवद गीता का एक रूसी संस्करण भेंट किया। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्तव्य, शाश्वत आत्मा और आध्यात्मिक मुक्ति के बारे में मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है।

भारत-रूस ने पंचवर्षीय आर्थिक मसौदे पर सहमति जताई

भारत और रूस ने अमेरिका द्वारा दंडात्मक शुल्क और प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए शुक्रवार को आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना पर सहमति जताई। वहीं, प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन में जारी युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। दुनिया भर की नजर मोदी और पुतिन के बीच होने वाली बातचीत पर रही जिसमें दोनों नेताओं ने आठ दशक से अधिक पुरानी भारत-रूस मित्रता को नई गति प्रदान करने की अपनी दृढ़ इच्छा प्रदर्शित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद यह मित्रता ''ध्रुव तारे'' की तरह अडिग बनी हुई है। दोनों देशों ने 2030 के आर्थिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के अलावा, स्वास्थ्य, गतिशीलता, खाद्य सुरक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

नेशनल हेराल्ड मामला :

डी.के. शिवकुमार को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के तहत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार को नोटिस जारी कर वित्तीय और लेनदेन संबंधी विवरण मांगा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि शिवकुमार के पास इस साल तीन अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित ''महत्वपूर्ण जानकारी होने की संभावना है''।

नोटिस 29 नवंबर को जारी किया गया था। नोटिस में ईओडब्ल्यू ने शिवकुमार को 19 दिसंबर तक पेश होने या मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

जांच अधिकारियों ने उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, कांग्रेस पार्टी के साथ उनके जुड़ाव और उनके या उनकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा 'यंग इंडियन' को कथित रूप से हस्तांतरित धनराशि का पूरा ब्योरा मांगा है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ के साथ तालमेल नहीं बिठाने के कारण निशाना बनाया जा रहा है और यह दर्शाता है कि वह कांग्रेस के लिए ''झटका झेलने'' वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शिवकुमार कांग्रेस नेताओं में ''सबसे अधिक सताए गए'' हैं लेकिन भाजपा उन्हें ''तोड़ने'' में सफल नहीं होगी।

नोटिस में कहा गया है, ''आपको सूचित किया जाता है कि ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस उपरोक्त मामले की प्राथमिकी की जांच कर रही है और आपके पास उपरोक्त मामले के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है।''

इंडिगो की सेवाओं में व्यवधान से हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी

- सरकार ने दिए जांच के आदेश
- डीजीसीए ने हस्तक्षेप करते हुए इंडिगो के पायलटों के लिए रात्रि ड्यूटी के कड़े नियमों से अस्थायी छूट दे दी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के राष्ट्रीय राजधानी से प्रस्थान करने वाली सभी उड़ानों सहित करीब 500 उड़ानें रद्द करने से देश भर में हजारों यात्री कई घंटों तक फंसे रहे और हवाई यात्रा शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी पटरी से उतरी नजर आई।

इंडिगो के पायलटों के उड़ान-समय के लिए नए नियमों की योजना बनाने में विफल रहने के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ। लोगों का गुस्सा बढ़ने और विपक्षी दलों के सरकार को घेरने के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हस्तक्षेप करते हुए इंडिगो के पायलटों के लिए रात्रि ड्यूटी के कड़े नियमों से अस्थायी छूट दे दी।

इंडिगो का संकट उन नए नियमों से खड़ा हुआ जिनके तहत पायलटों के साप्ताहिक आराम की जरूरत के समय को 12 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। साथ ही सप्ताह में केवल दो बार रात में लैंडिंग की अनुमति दी गई है, जो पहले छह हुआ करती थी।

इंडिगो ने इन व्यवधानों के लिए '' गलत फैसलों और योजनागत कमियों '' को जिम्मेदार ठहराया है।

दिल्ली हवाई अड्डे ने घोषणा की कि शुक्रवार को इंडिगो की करीब 235 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चेन्नई हवाई अड्डे ने भी प्रमुख महानगरीय गंतव्यों के लिए सभी उड़ानें शाम छह बजे तक रोक दी हैं।

हवाई अड्डा सूत्रों ने बताया कि इंडिगो ने मुंबई में 104, बेंगलूरु में 102 और हैदराबाद में 92 उड़ानें रद्द की गईं।

पान मसाला पर उपकर लगाने वाले विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दी

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा ने पान मसाला पर उपकर लगाने के प्रावधान वाले विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' पर हुई चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद सदन ने विभिन्न संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह किसी भी वित्त मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि राजस्व बढ़ाया जाए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में मांग को पूरा किया जा सके, लेकिन यहां एक सरकार है जिसने कर के दायरे को घटाया है। उन्होंने कहा कि आयकर की सीमा में भारी छूट दी गई है और 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर देने की जरूरत नहीं है। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में व्यापक बदलाव किया गया है ताकि चीजें किफायती हों। उनका कहना था कि आयकर की सीमा बढ़ाने से लोगों के हाथ में एक लाख करोड़ रुपए बचे हैं।

युद्धभ्यास 'हरिमऊ शक्ति' राजस्थान में शुरू

नई दिल्ली/भाषा। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया को समन्वित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को राजस्थान में युद्धाभ्यास की शुरुआत की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त युद्धाभ्यास 'हरिमऊ शक्ति' का पांचवां संस्करण 5 से 18 दिसंबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है।

रेपो दर में एक चौथाई की कटौती, आवास और वाहन ऋण होगा सस्ता

- भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को नीतिगत रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की।
- आरबीआई ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 के भी पार चले जाने से जुड़ी आशंकाएं दरकिनार करने की कोशिश की है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को नीतिगत रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की। इससे घर, वाहन और अन्य कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है।

इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों में एक लाख करोड़ रुपए की नकदी डालने की भी घोषणा की। इससे अर्थव्यवस्था को अमेरिकी शुल्क के प्रभाव से सुरक्षित रखने और रुपए की कीमत में आई गिरावट से निपटने में मदद मिलेगी।

आरबीआई की छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। यह फरवरी 2025 के बाद से चौथी कटौती है और अब तक कुल 1.25 प्रतिशत कटौती हो चुकी है। रेपो दर में छह महीने के अंतराल के बाद की गई इस कटौती से आवास, वाहन और अन्य उपभोक्ता ऋणों के सस्ते होने का रास्ता खुल गया है।

दरअसल रेपो दर में कटौती का सीधा असर बैंकों की उधारी लागत पर होता है। बैंकों को अब केंद्रीय बैंक से सस्ते में उधार मिलेगा लिहाजा वे एमसीएलआर (कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर) और अन्य ऋण दरों में कमी कर सकेंगे। इससे घर, वाहन और व्यावसायिक ऋणों की मासिक किस्तें घटेंगी।

रेपो दर में इस कटौती से आरबीआई ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 के भी पार चले जाने से जुड़ी आशंकाएं दरकिनार करने की कोशिश की है। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में पांच प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है जो एशिया की सभी मुद्राओं के बीच सबसे खराब प्रदर्शन है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली एमपीसी ने मौद्रिक नीति के रुख को 'तटस्थ' बनाए रखने का भी फैसला किया। इसका मतलब है कि भविष्य में भी दर कटौती की गुंजाइश बनी हुई है।

|| श्री गणेशाय नमः || || श्री राणी सत्यै नमः || || श्री हनुमंते नमः ||
श्री दादी धाम प्रचार समिति, बेंगलोर
द्वारा आयोजित
श्री दादीजी की विशाल भजन संध्या एवं वार्षिकोत्सव
रविवार, 7 दिसम्बर 2025, अपराह्न 3 बजे से, आरती रात्रि 9 बजे
विशेष आकर्षण: भव्य श्रृंगार, अखंड ज्योति, चुनड़ी उत्सव, गजरा उत्सव, मेहंदी उत्सव, छप्पन भोग, लक्की डॉ नि:शुल्क कूपन (झुंझुनू धाम)
* आमंत्रित कलाकार *

मोनू मोर, कोलकाता
* कार्यक्रम स्थल *
श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथ ट्रस्ट
नं. 554, 555 - HBCS, आइडियल होम्स लेआउट, राजराजेश्वरी नगर, बेंगलोर
* आमंत्रित कलाकार *

वर्षा सोनी, सूरत
आप सपरिवार, ईष्ट - मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं।
* कार्यक्रम संयोजक * विनय राय : 96119 30686 बिमल जिलोका : 93412 58465
* कार्यक्रम सहसंयोजक * अनूप अग्रवाल : 93425 39940, शंकर सुल्तानिया : 81054 78349 राजेन्द्र बजाज : 98807 11225, अजय सिंघानिया : 93420 15693
आयोजक : श्री दादी धाम प्रचार समिति, बेंगलोर
अध्यक्ष : शिवकुमार टेकड़ीवाल 93425 04568 सचिव : संजय चौधरी 97411 25482 कोषाध्यक्ष : प्रकाश चौधरी 93412 10277
कार्यक्रम स्थल पर महाप्रसाद की व्यवस्था है ।

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

भीड़ की पीड़

कर रहे भीड़ पर जो स्यापा,
वे भीड़ जुटाऊ नेता हैं।
निज नीड़ भीड़ से बना रहे,
भड़काऊ भीड़ प्रचेता हैं।
ये भीड़ बनी नैया जिनकी,
वे उनके घोषित खैता हैं।
बिन भीड़ जुटा लड़ लें चुनाव,
यदि सचमुच कुशल प्रणेता हैं।।

वक्फ पंजीकरण की समयसीमा नहीं बढ़ेगी, मुत्तवलियों को तीन महीने की राहत मिलेगी : रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

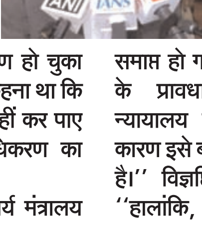

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की संभावना से शुक्रवार को इनकार किया और कहा कि पंजीकरण नहीं कर पाने वाले 'मुत्तवलियों' (वक्फ का देखभाल करने वाले) को तीन महीने तक जुर्माने और किसी कठोर सजा से राहत दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार सुबह तक 1.51 लाख संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका था। मंत्री का यह भी कहना था कि जो लोग पंजीकरण नहीं कर पाए हैं वो वक्फ न्यायाधिकरण का रुख कर सकते हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य छह महीने की समय सीमा समाप्त हो गई है और अधिनियम के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के कारण इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है।'' विज्ञप्ति में कहा गया है, ''हालांकि, मुतवल्लियों की चिंताओं को समझते हुए मंत्री ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय मानवीय और सुविधाजनक उपाय के रूप में अगले तीन महीनों तक कोई जुर्माना नहीं लगाएगा और कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा।'' मंत्रालय ने कहा, ''जो मुतवल्ली 6 दिसंबर, 2025 को रात 11:59:59 बजे तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थ हैं, वे वक्फ न्यायाधिकरण का रुख कर सकते हैं, जिसके समयसीमा बढ़ाने का कानूनी अधिकार है।

इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ को 'सीईओ ऑफ़ द ईयर' पुरस्कार मिला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बिनोद कुमार को तमिलनाडु बिज़नेस लीडर ऑफ़ द ईयर इंडस्ट्री वाइज अवॉर्ड्स 2025 में प्रतिष्ठित 'सीईओ ऑफ़ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ताज क्लब हाउस में प्रदान किया गया।ङ्गइस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए स्वतंत्र जूरी ने बिनोद कुमार का चयन व्यापक मूल्यांकन के बाद किया, जो रणनीतिक नेतृत्व, व्यावसायिक दक्षता, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, हितधारकों के लिए मूल्य सृजन तथा समाज के कल्याण में सार्थक योगदान जैसे मानकों पर आधारित था।

नौसेना दिवसः 'संबंध' और बीटिंग रिट्रीट में दिखाई दी अटूट प्रतिबद्धता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। नौसेना दिवस के जश्न के तहत 'संबंध' और बीटिंग रिट्रीट समारोह 4 दिसंबर को नेवी हाउस, कारवार में आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत थे। शाम का मुख्य आकर्षण बीटिंग रिट्रीट समारोह था, जिसमें नेवी बैंड ने युद्ध और औपचारिक संगीत दोनों प्रस्तुत किए। सूर्यास्त के समय कारवार नेवल हार्बर में लंगर डाले हुए नौसैनिक युद्धपोतों ने भव्य पृष्ठभूमि प्रस्तुत की, जो राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।कारवार के नेवी चिल्ड्रन स्कूल के विद्यार्थियों और नेवल कम्युनिटी के कलाकारों के प्रदर्शन ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को पेश करते हुए जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में नौसैना के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे।

पाकिस्तान में स्कूली छात्राओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप

कराची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कुछ हिंदू स्कूली छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा गया, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नवंबर के अंत में, सिंध के मिरपुर साक्रो में स्थित सरकारी उच्च विद्यालय की कुछ हिंदू छात्राओं के माता-पिता ने मीडिया को बताया था कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने कथित रूप से हिंदू छात्राओं से कहा था कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इस्लाम धर्म अपना लें।

केरल में दोनों पक्ष 'लड़ाई' का दिखावा करते हैं, राज्य का विकास नहीं चाहते : रेल मंत्री वैष्णव

नई दिल्ली/भाषा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में दावा किया कि कि केरल की दो मुख्य पार्टियां (कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) राज्य में विकास नहीं चाहतीं। इसके साथ ही उन्होंने दोनों पार्टियां पर संसद में लड़ाई का दिखावा करने का आरोप लगाया।

उच्च सदन में रेल मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि केरल में कई परियोजनाओं पर काम राज्य सरकार के सहयोग के अभाव के कारण अटका हुआ है। उन्होंने कई रेलवे अंडर-ब्रिज के काम का उदाहरण दिया, जो भूमि उपलब्ध न होने के कारण अटका हुआ है, जिसे राज्य सरकार को उपलब्ध कराना होता है। उन्होंने सदन से कहा, यह तथाकथित लड़ाई उनके और उनके (केरल की दो प्रमुख पार्टियों के) बीच बहुत दिलचस्प है। यह एक दिखावा लगता है, जो मूल रूप से केरल के लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। वास्तविकता यह है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केरल में रेलवे नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वैष्णव ने आरोप लगाया, ये दोनों पक्ष हमेशा लड़ाई का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर, वे सब जुड़े हुए हैं। वे सब एक ही लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं, और वह लक्ष्य है केरल का विकास न हो। रेल मंत्री कांग्रेस सांसद जेबी माथेर द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, जिन्होंने राज्य सरकार पर विकास पहल में सहयोग न करने का आरोप लगाया। इस पर माकपा सदस्यों ने उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और उनका प्रतिवाद किया।

वैष्णव ने कहा, केरल के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और 372 करोड़ रुपए के मामूली बजट से बढ़कर अब 3,042 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो पहले की तुलना में आठ गुना से अधिक है। जब रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय द्वारा केरल में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का विवरण दिया और राज्य सरकार पर टिप्पणी की, वाम सांसदों ने उन्हें बाधित करने की कोशिश की। मंत्री ने कहा, वे (वाम सदस्य) विकास कार्य सुन नहीं सकते। उन्हें विकास कार्य में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कई परियोजनाएं राज्य सरकार के सहयोग के अभाव के कारण रुकी हुई हैं।

कार्तिगई दीप जलाने से जुड़े मामले पर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायालय सहमत

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने तिरुपरमकुंद्रम में स्थित पत्थर के एक दीप स्तंभ 'दीपथून' में दरगाह के निकट अरुलमिघु सुब्रमणिय स्वामी मंदिर के श्रद्धालुओं को परंपरागत कार्तिगई दीपम' दीपक जलाने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील की दलीलों पर गौर किया और कहा कि याचिका को पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा।

पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किए जाने पर प्रतिवादियों के एक वकील ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह केवल उच्च न्यायालय को यह बताने के लिए अनावश्यक नाटक कर रही है कि यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। हालांकि, सरकारी वकील ने कहा कि वह मामले का केवल उल्लेख कर रहे थे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम विचार करेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बृहस्पतिवार को मदुरै जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा दायर एक अंतर-न्यायालयी अपील खारिज कर दी और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें श्रद्धालुओं को दीपथून में 'कार्तिगई दीपम' दीप जलाने की अनुमति दी गई थी।

मीटिंग

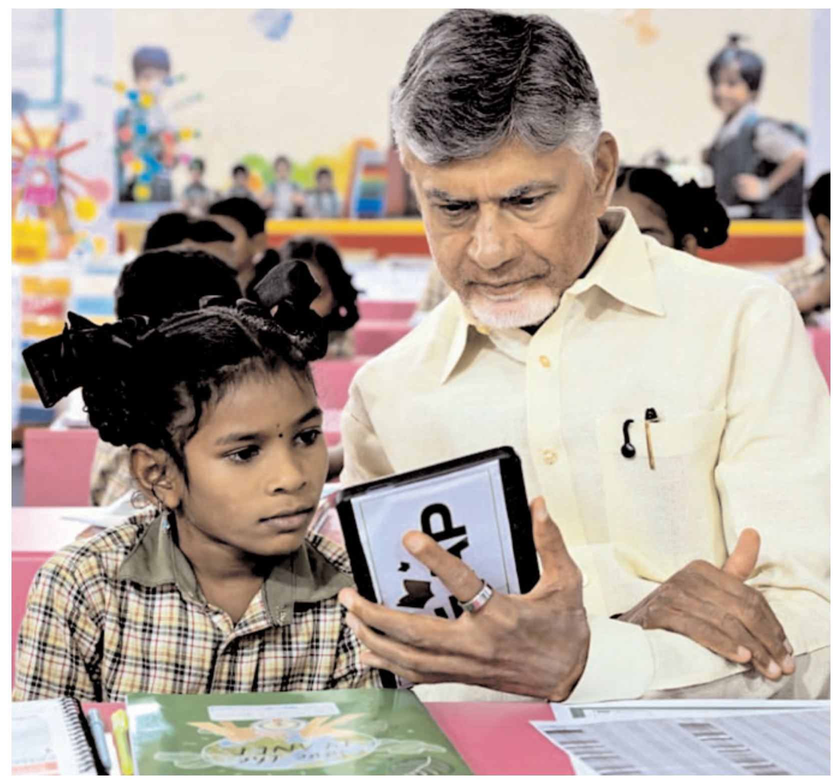

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पार्वतीपुरम मान्यम जिले के भीमुनिपट्टनम में सरकारी मॉडल स्कूल में हुई मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग के दौरान एक छात्र के साथ।

बालू ने न्यायाधीश पर की टिप्पणी, लोकसभा में हंगामा

नई दिल्ली/भाषा

द्रमुक के वरिष्ठ नेता टी आर बालू ने तमिलनाडु में एक दरगाह के निकट स्थित मंदिर में 'कार्तिगई दीपम' से जुड़ा मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा में उठाया और मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर टिप्पणी की, जिस पर सत्तापक्ष ने तीखी आपत्ति जताई।

बालू ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि एक दल द्वारा सांप्रदायिक टकराव की स्थित पैदा की जा रही है। उन्होंने इस मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीश को एक संगठन से जोड़कर उनका उल्लेख किया।

इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि बालू असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने (बालू ने) किसी न्यायाधीश और न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणी की थी। यह आपके (बालू) और आपके दल के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।

रीजीजू का कहना था, हमें कड़ी आपत्ति है। यह गलत परिपाटी है...सदन ऐसे नहीं चलेगा।

पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने बालू से कहा, आप जानते हैं कि मामला अदालत के विचाराधीन है। आपने जो कहा वह आपत्तिजनक है, उसे कार्यवाही से हटाया जाता है। आप किसी न्यायाधीश पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री और तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेता एल मुरुगन ने भी बालू की टिप्पणी पर विरोध जताया और कहा कि वहां जो हुआ है, वह एक न्यायपालिका के आदेश के बाद हुआ। उन्होंने बालू पर न्यायपालिका पर आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल का दावा किया।

गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने दरगाह के पास स्थित मंदिर में 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

उच्चतम न्यायालय ने तिरुपरमकुंद्रम में स्थित पत्थर के एक दीप स्तंभ 'दीपथून' में दरगाह के निकट अरुलमिघु सुब्रमणिय स्वामी मंदिर के श्रद्धालुओं को परंपरागत कार्तिगई दीपम' दीपक जलाने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बृहस्पतिवार को मदुरै जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा दायर एक अंतर-न्यायालयी अपील खारिज कर दी और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें श्रद्धालुओं को दीपथून में 'कार्तिगई दीपम' दीप जलाने की अनुमति दी गई थी।

जब आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ तो एकल न्यायाधीश ने तीन दिसंबर को एक और आदेश पारित कर श्रद्धालुओं को स्वयं दीप जलाने की अनुमति दे दी तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके बाद राज्य सरकार ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया।

राजग सरकार ने एमएसपी दोगुना किया, फसल खरीद चार गुना बढ़ाई : शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली/भाषा

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने न केवल फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उनकी उत्पादन लागत से दोगुना तय किया है, बल्कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संपग्र) सरकार की तुलना में खरीद भी चार गुना बढ़ाई है।

उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान चौहान ने फसलों के एमएसपी से संबंधित पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पिछली संप्रग सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत बढ़ोतरी देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2019 में इन सिफारिशों को स्वीकार करने और उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत 'मार्जिन' के साथ एमएसपी देने का निर्णय किया।

एमएसपी का मुद्दा उठाते हुए राजस्थान से कांग्रेस सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक ने पूछा कि क्या किसान एमएसपी के तहत कानूनी गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार इस पर कोई कानून लाने पर विचार कर रही है और क्या वह ऐसी गारंटी देने के लिए तैयार है?

चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लागत कम करने के प्रयास किए हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों से फसलों की खरीद सही कीमत पर हो। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एमएसपी को संप्रग सरकार की तुलना में दोगुना कर दिया है।

कृषि मंत्री ने कई उदाहरण देते हुए कहा कि संप्रग सरकार ने 2013-14 में धान के लिए 1,310 रुपए एमएसपी दिया था, जबकि मोदी सरकार ने 2,369 रुपए देने का निर्णय लिया है। इसी तरह, ज्वार (सफेद बाजरा) का खरीद मूल्य संप्रग शासनकाल के दौरान 1,500 रुपए से बढ़ाकर 3,699 रुपए कर दिया गया है।

चौहान ने 10 साल के संप्रग शासन (2004 2014) के दौरान फसल खरीद की तुलना वर्तमान राजग शासन से करते हुए दावा किया कि फसल खरीद चार गुना बढ़ी है।

वासनिक ने कहा कि कृषि मंत्री ने लंबा उत्तर दिया, लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया। कांग्रेस सदस्य के अनुसार, राजग के 11 वर्षों के शासन में 1,12,000 किसानों ने आत्महत्या की है और कृषि ऋण 28.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक रैली में घोषणा की थी कि सोयाबीन को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीदा जाएगा, लेकिन यह कीमत अभी तक नहीं दी गई है।

वासनिक ने सरकार द्वारा एमएसपी तय करने में इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले पर सवाल किया। इस पर चौहान ने दोहराया कि संप्रग सरकार ने स्वामीनाथन सिफारिश को खारिज कर दिया था, जबकि राजग उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ के साथ एमएसपी देता है।

कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार, जो एमएसपी योजना के तहत रिकॉर्ड मात्रा में फसलों की खरीद कर रही है, ने तूर, मसूर और उड़द आदि के उत्पादन का 100 प्रतिशत खरीदने का निर्णय लिया है। उन्होंने कांग्रेस-शासित कर्नाटक सरकार पर फसल खरीद मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

चौहान ने यह भी कहा कि जहाँ संप्रग सरकार ने किसानों से सब्जियाँ और फल नहीं खरीदे, वहीं उनकी सरकार ने बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत टमाटर, आलू और प्याज के साथ-साथ सेब, अंगूर, लाल मिर्च और अदरक भी खरीदे हैं। उन्होंने कहा, हम कुछ फसलों पर एमएसपी से 50 प्रतिशत से अधिक दे रहे हैं।

प्रश्नकाल के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने पूरक प्रश्न पूछा कि क्या एमएसपी के तहत शामिल फसलों की संख्या बढ़ाने की मांग आयी है और क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने एमएसपी कवरेज बढ़ाने की सिफारिश की गयी है?

माकपा सदस्य ने यह भी पूछा कि क्या 2017 18 से केरल के लिए धान खरीद को लेकर 1,206.69 करोड़ रुपए की राशि केंद्र के पास बकाया है, और यदि हाँ, तो सरकार इसे कब जारी करेगी।

प्रदर्शन

अमृतसर में शुक्रवार को किसान मज़दूर मोर्चा, पंजाब चैप्टर द्वारा केंद्र सरकार के ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 और दूसरे मुद्दों के खिलाफ़ राज्य भर में 'रेल रोको' प्रोटेस्ट के दौरान किसान रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते हुए।

जागरूकता कैंपेन

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य विधानसभा में डेझ और जयराम ठाकुर और अन्य लोगों के साथ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में चिट्टा विरोधी जागरूकता कैंपेन के दौरान नारे लगाते हुए।

राष्ट्रीय पुरुष आयोग गठित करने के प्रावधान वाला निजी विधेयक राज्यसभा में पेश

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में शुक्रवार को कुल 58 निजी विधेयक पेश हुए जिनमें राष्ट्रीय पुरुष आयोग गठित करने के प्रावधान वाला एक विधेयक शामिल है।

उच्च सदन में शुक्रवार होने के बाद भोजनावकाश के बाद दोपहर दो बजे से गैर सरकारी कामकाज हुआ। इसके तहत आम आदमी पार्टी के डॉ अशोक मित्तल ने पुरुष आयोग विधेयक पेश किया, जिसमें पुरुषों के अधिकार और कल्याण के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है।

मित्तल द्वारा पेश किए गए विधेयक में पुरुषों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और एक निवारण तंत्र की सिफारिश करने का प्रावधान किया गया है। इसमें पुरुषों को प्रभावित करने वाले वर्तमान कानूनों एवं नीतियों की समीक्षा का भी सुझाव दिया गया है। आप सदस्य ने दो अन्य निजी विधेयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अधिकार विधेयक और आवारा एवं जगली पशुओं के हमले (निवारण और कल्याण) विधेयक भी पेश किए।

तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने तीन निजी विधेयक पेश किए। इनमें राष्ट्रीय मीडियाकर्मी सुरक्षा समिति विधेयक, सरोगेसी विधि (संशोधन) विधेयक और महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) संशोधन विधेयक शामिल हैं।

उच्च सदन में भाजपा के डॉ भीम सिंह ने (2), भारत राष्ट्र समिति के केआर सुरेश रेड्डी (1), कांग्रेस की जेबी माथेर हीशम (2), तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले (2), बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा (3), मनोनीत सुधा मूर्ति (1), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन (3), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की फौजिया खान (3), तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन (3), भाजपा के अजीत माधवराव गोपछड़े (3), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास (3), राष्ट्रीय जनता दल के ए डी सिंह (3), भाजपा के सुजीत कुमार (3), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी (3), भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी (3), द्रमुक के आर गिरिराजन (1), द्रमुक की कानिमोझी एनवीए सोमू (3), स्वाति मालीवाल (2), भाजपा के धनंजय भीमराव महादिक (3), और भाजपा के ईरण्ण कडाडी (3) और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा (3) ने भी निजी विधेयक पेश किए।

बेंगलूरु में शुक्रवार को फ्लाइट में रुकावट के बीच केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट पर इंडिगो की अपनी फ्लाइट के बारे में पूछते पैसेंजर। पायलट-रोस्टरिंग की दिक्कतों की वजह से इंडिगो का ऑपरेशन ठप हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ीं। कई पैसेंजर तीन दिन तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे।

उड़ान सेवा में बाधा ने नवविवाहित जोड़े को स्वागत समारोह में ऑनलाइन शामिल होने पर मजबूर किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुब्बली। मेघा क्षीरसागर और संगम दास की शादी के बाद स्वागत समारोह (रिसेप्शन) तीन दिसंबर को हुबली शहर में रखा गया था। आयोजन स्थल को पूरी तरह सजाया गया था और आमंत्रितों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार थे, लेकिन अचानक विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ान रद्द होने के कारण इस नवविवाहित जोड़े को उनके सम्मान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होने पर मजबूर कर दिया। नवविवाहित जोड़े का स्वागत समारोह तीन दिसंबर को तय किया गया था, लेकिन शीर्ष विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाएं बाधित होने के कारण (मुख्य रूप से चालक दल की समस्याएं) वे हुबली नहीं पहुंच सके, जहां इसका आयोजन किया गया था।

नवविवाहित जोड़ा भुवनेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वागत समारोह में शामिल हुआ, मेहमानों का अभिवादन किया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो पाने के लिए माफी मांगी। परिवार के अनुसार, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बेंगलूरु में काम करते हैं। बुधवार को दुल्हन के पैतृक शहर हुबली में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।

अपने इस खास दिन का हिस्सा बनने के लिए, इस जोड़े ने दो दिसंबर के लिए भुवनेश्वर-बेंगलूरु-हुबली मार्ग पर इंडिगो की उड़ान के टिकट बुक किए थे। कुछ रिश्तेदारों ने भुवनेश्वर-मुंबई-हुबली मार्ग पर भी टिकट बुक किए थे। हालांकि, परिचालन संबंधी व्यवधानों के कारण, इंडिगो की उड़ानें दो दिसंबर की सुबह नौ बजे से तीन दिसंबर की सुबह तक लगातार देरी से चल रही थीं और अंततः रद्द कर दी गईं। दुल्हन के पिता अनिल कुमार क्षीरसागर ने 'पीटीआई-वीडियो' को बताया, मेरी बेटी की शादी 23 नवंबर को हुई थी और हमने हुबली में अपने पैतृक स्थान पर यहां के लोगों के लिए एक स्वागत समारोह (रिसेप्शन) का आयोजन किया था। उड़ान में देरी होती रही और आखिरी समय में, लगभग सुबह चार बजे उड़ान रद्द कर दी गयी। अब उसके बाद हम क्या कर सकते थे। हमें कुछ समाधान निकालना था। तब मैंने ऑनलाइन माध्यम से स्वागत समारोह आयोजित करने का फैसला किया। मैंने तुरंत एक स्क्रीन की व्यवस्था की और अपनी बेटी और दामाद को डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा।

उन्होंने केंद्र सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया, ताकि जनता को परेशानी न हो। क्षीरसागर ने कहा, हमें नहीं पता कि इंडिगो के साथ क्या समस्या है। मेरी बेटी और दामाद इंडिगो की उड़ान से आने वाले थे, लेकिन वह रद्द हो गई। इसके लिए सिर्फ इंडिगो को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सरकार को समझना चाहिए कि आपात स्थिति में ही लोग हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। जब ङ्कङ्कप्रधानमंत्री की उड़ान रद्द हो जाती है, तो उन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है। ऐसा ही हम आम लोगों के लिए क्यों नहीं किया जाता? हमारे सामने भी आपात स्थिति आती है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। चूंकि नवविवाहित जोड़ा हुबली नहीं पहुंच सका, इसलिए दुल्हन के माता-पिता नवविवाहित जोड़े के स्थान पर बैठे और रस्में निभाईं, जबकि दूल्हा और दुल्हन भुवनेश्वर में तैयार होकर ऑनलाइन अपने भव्य रिसेप्शन में शामिल हुए।

बेंगलूरु से मुंबई और दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ानें आधी रात तक रद्द, यात्री फंसे

बेंगलूरु। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाले 'बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड' ने शुक्रवार को यात्रियों को सूचित किया कि बेंगलूरु से मुंबई और दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ानें पांच दिसंबर की रात 11 बजकर 59 मिनट तक के लिए रद्द कर दी गयी हैं। इन उड़ानों के रद्द होने से कई यात्री फंस गये। पटना में अपने भाई की सगाई में शामिल होने जा रही एक महिला हवाई अड्डे पर अपने शिशु को संभाले हुए थी। एक अन्य यात्री अपने पिता की अस्थियों से भरा कलश लिए हरिद्वार पहुंचने का इंतजार कर रहा था और सबरीमला जा रहे भगवान अयप्पा के भक्त उड़ानों के रद्द हो जाने से खासे परेशान दिखाई दिये। 'बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड' ने एक यात्री परामर्श में बताया कि अन्य गंतव्यों की इंडिगो की उड़ानों के लिए यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले विमानन कंपनी से नवीनतम स्थिति की पुष्टि कर लेनी चाहिए। 'एक्स' पर जारी परामर्श में बताया गया, हमारी मौके पर मौजूद टीमें इंडिगो और सभी परिचालन भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही हैं ताकि असुविधा को कम किया जा सके और इस व्यवधान के दौरान यात्रियों की सहायता की जा सके। हम आपके समन्वय और सहयोग के लिए आभारी हैं।

भाजपा नेता आर अशोक ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता आर. अशोक ने शुक्रवार को कहा कि मूर्खता क्षम्य है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में 'बेशर्म' होना अक्षम्य है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने दावा किया कि अपने कार्यकाल के मात्र 30 महीनों में ही कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार संबंधी विवादों के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विपक्ष के नेता बृहस्पतिवार को 'एक्स' पर सिद्धरमैया की उस पोस्ट का जवाब दे रहे थे, जिसमें सिद्धरमैया ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा था कि उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति वीरप्पा का '63 प्रतिशत भ्रष्टाचार' वाला दावा उनकी नवंबर 2019 की रिपोर्ट पर आधारित था, जब भाजपा के बी एस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री ने कहा था,

लेकिन अशोक ने उप लोकायुक्त के बयान को ठीक से समझे बिना ही भाजपा के पापों का बोझ हमारे सिर पर डाल दिया है और वास्तव में उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अशोक ने शुक्रवार को सिद्धरमैया को संबोधित करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट कर जवाब दिया, राजनीति में मूर्ख कहलाना एक बात है, उसे माफ किया जा सकता है लेकिन सार्वजनिक जीवन में, खासकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, किसी को कभी बेशर्म नहीं होना चाहिए।

अशोक ने कहा कि यह देखते हुए कि मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया था कि वाल्मीकि विकास निगम में 87 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री सदन के पटल के अंदर इतनी बड़ी अनियमितता को स्वीकार करता है, तो तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही की स्वाभाविक अपेक्षा होती है।

उन्होंने कहा, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाय आप ऐसे पद पर बने हुए हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कर्नाटक के लोग इसे सरासर बेशर्मी न कहें, तो और क्या कहें। इससे पहले, बृहस्पतिवार को अशोक ने राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले और आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने मांग की थी। उन्होंने उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति वीरप्पा के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 63 प्रतिशत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसके बाद सिद्धरमैया ने भाजपा नेता पर पलटवार किया था।

शिवकुमार ने 'कार्टियर वॉच' पर सफाई दी, भाजपा नेता पर किया पलटवार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके. शिवकुमार ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता चलवाडी नारायणस्वामी पर पलटवार करते हुए लोकायुक्त को सौंपे गए हलफनामे में महंगी 'कार्टियर' कलाई घड़ी के रिकॉर्ड के साथ सफाई दी। उन्होंने खुद को एक 'साफ सुथरा व्यक्ति' बताते हुए पूछा कि क्या उन्हें या मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अपनी पसंद की घड़ी पहनने का अधिकार नहीं है? विधान परिषद में विपक्ष के नेता नारायणस्वामी ने महंगी घड़ियों के बारे में सवाल उठाया था, जिसके एक दिन बाद शिवकुमार ने यह सफाई दी। शिवकुमार ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, चलवाडी नारायणस्वामी, कृपया मेरे द्वारा लोकायुक्त को प्रस्तुत हलफनामे पर एक नजर डालें।

इस पोस्ट में 28 अक्टूबर को लोकायुक्त के पास घोषित संपत्ति के दस्तावेज भी शामिल हैं, जिनमें नौ लाख रुपये की रोलेक्स घड़ी और क्रमशः 23,90,246 रुपये और 12,06,000 रुपये की दो 'कार्टियर' कलाई घड़ियों का उल्लेख है। उपमुख्यमंत्री ने कहा, जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का अपनी सुविधा के लिए झूठ बोलना न केवल गलत है, बल्कि आपकी (नारायणस्वामी) ईमानदारी को भी कमजोर करता है। उन्होंने कहा, मैं एक साफ सुथरा व्यक्ति हूं और मैंने सच को खुलेआम साझा किया है। क्या मुझे या यहां तक ङ्कङ्कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को भी अपनी पसंद की घड़ी पहनने का अधिकार नहीं है? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप निराधार टिप्पणियां करने से बचें और अपने संवैधानिक अधिकार का बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से प्रयोग करें। शिवकुमार ने कहा कि सभी विवरण रिकॉर्ड में हैं और अगर भाजपा नेता चाहें तो वे लोकायुक्त कार्यालय में आकर स्वयं हलफनामे की पुष्टि कर सकते हैं।

जब शिवकुमार, दो दिसंबर को नाश्ते के लिए सिद्धरमैया के घर गये तब दोनों शीर्ष नेताओं ने कथित रूप से एक जैसी कार्टियर घड़ियां पहनी हुई थीं। विपक्षी भाजपा ने महंगी घड़ियों की आलोचना की और इस पर सवाल उठाए थे।

कार्तिगई दीपम विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग केवल विकास और रोजगार चाहते हैं

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के. स्टालिन ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और हिंदुत्ववादी संगठनों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि मदुरै के लोग केवल विकास और रोजगार चाहते हैं।

तिरुप्परनकुंद्रम पर्वत पर पत्थर के एक दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम का दीपक जलाने को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान और कानूनी लड़ाई के बीच स्टालिन ने कहा: लोग तय करेंगे कि मदुरै की जरूरत विकास की राजनीति है या... महज राजनीति। स्टालिन के इस बयान को भाजपा की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल परियोजना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नए उद्योगों और रोजगार के अवसरों का उल्लेख किया और कहा कि मदुरै में रहने वाले लोग केवल विकास को बढ़ावा देने वाली राजनीति चाहते हैं।

मक्कल निधि मैयम (एमएनएम) के संस्थापक नेता कमल हासन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि धर्मों का मूल आधार मानवता का सम्मान करना है और हमें ऐसी किसी भी कार्ययोजना का शिकार नहीं बनना चाहिए जो शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती हो... ज्ञान ही शक्ति है।

बेंगलूरु में एक व्यक्ति मेट्रो ट्रेन के सामने कूदा, मौत

बेंगलूरु। बेंगलूरु के केंगेरी मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के सामने कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिससे पर्पल लाइन पर मेट्रो सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित हुईं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान 38 वर्षीय शांतगौड़ पुलिसपाटिल के रूप में हुई है। यह घटना सुबह सवा आठ बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शांतगौड़ ने ट्रेन से टकराने के लिए सही समय पर छलांग लगाई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पैरामेडिकल टीम के साथ मिलकर शव को तुरंत पटरियों से हटाया। इस घटना के बाद पर्पल लाइन पर मैसूर रोड से चल्लाघट्टा तक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि बाद में सेवाओं को बहाल कर दिया गया। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, सुबह 9:40 बजे तक ज्ञान भारती और चल्लाघट्टा के बीच की सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। अब पूरे पर्पल लाइन पर ट्रेन परिचालन सामान्य समय-सारणी के अनुसार हो रहा है। केंगेरी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने 1.75 करोड़ रुपये की लाल चंदन की लकड़ी जब्त की

बेंगलूरु। बेंगलूरु पुलिस ने अंतरराज्यीय तस्करी के दो मामलों का पर्दाफाश करते हुए 1.75 करोड़ रुपये मूल्य की लाल चंदन की लकड़ी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर हुलीमावु पुलिस थाने और आर टी नगर पुलिस थाने के सीमा क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से लाल चंदन ला रहे वाहनों को रोका।

वृहद गीतोत्सव में सात दिसंबर को शामिल होंगे पवन कल्याण

उडुपी (कर्नाटक)। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण यहां कृष्णा मठ में चल रहे वृहद गीतोत्सव के समापन समारोह में सात दिसंबर को शामिल होंगे। आयोजकों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुतिगे मठ के महंत सुगणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी के चतुर्थ विश्व गीता पर्याय के तहत पुतिगे मठ के तत्वावधान में महीने भर से चल रहे गीतोत्सव का सात दिसंबर को समापन होगा। समापन समारोह शाम चार बजे प्रस्तावित है। पुतिगे मठ के दीवान नागराजा आचार्य और मठ प्रशासन के सचिव प्रसन्न आचार्य ने यह घोषणा करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति से समापन समारोह का महत्व बढ़ेगा। पिछले चार सप्ताह के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आकर्षित हुए हैं।

उद्घाटन

मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने शुक्रवार को बेंगलूरु के गांधी नगर में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया।

सबरीमला सोना चोरी मामले में अंतरराष्ट्रीय गिरोह के संबंधों की जांच हो: कांग्रेस नेता चेन्निथला

कोट्टायम/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने शुक्रवार को कहा कि वह सबरीमला सोना चोरी मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को पत्र सौंप उससे प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में शामिल एक वैश्विक गिरोह से संबंधों की जांच का अनुरोध करेंगे।

चेन्निथला ने यहां पत्रकारों से कहा कि इस मामले में प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी सुभाष कपूर के नेतृत्व वाले एक समूह से जुड़े लेन-देन के संकेत मिले हैं लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सबरीमला से चुराई गई सोने की प्लेटों की कीमत प्राचीन वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय 'काला बाजार' में लगभग 500 करोड़ रुपए तक हो सकती है।

कांग्रेस राहुल ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से बचा रही है : विजयन

कोच्चि/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपने निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को बचा रही है और कहा कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी इस विधायक को पकड़ने के लिए पुलिस प्रभावी कदम उठा रही है।

विजयन ने यह भी कहा कि कांग्रेस में ऐसे अन्य विधायक भी हैं, जो इसी तरह के आरोप का सामना कर रहे हैं या जिन्हें अन्य अपराधों के लिए जेल हो चुकी है, लेकिन वे अब भी पार्टी में बने हुए हैं। उन्होंने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा, एल्डहोस कुन्नापिल्ली और एम. विंसेंट अब भी पार्टी में बने हुए हैं।

नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/शिमला। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा शिमला में आयोजित 196वीं ईएसआई बैठक के दौरान नियोक्ता व कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना एसपीआईईई (स्प्री) 2025 को मंजूरी दी गई। मुख्यालय ने अपने परिपत्र के अनुसार उक्त योजना को 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कार्यान्वित किया है। अपंजीकृत नियोक्ताओं, संविदा और अस्थायी सहित सभी नियोक्ताओं का बिना किसी निरीक्षण या पिछला बकाया की बाध्यता रहित इस योजना में पंजीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी नव पंजीकृत कामगार को उसकी पंजीकरण तिथि से योजना के तहत व्याप्त माना जाएगा। योजना में कोई भी व्याप्त नियोक्ता एवं कामगार कराबी निगम अधिनियम के तहत किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई / चूककर्ता बकायों के लिए बाध्य नहीं होगा। इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा कामगार वर्ग तक पहुंच बढ़ाना है, ताकि ज्यादा नियोक्ता, कामगार और उनके परिवार इससे फायदा उठा सकें।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
चतुर्थ तल, बंगला साहिब रोड, काली मंदिर के पीछे, गोल मार्केट, नई दिल्ली - 110 001
AADHAAR

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु में सहायक अनुभाग अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति (बाह्य सेवा शर्तों) आधार पर भरने हेतु रिक्ति परिपत्र।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु में सहायक अनुभाग अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति (बाह्य सेवा शर्तों) आधार पर भरने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निदेशक (मा.सं.), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय, तृतीय तल, साउथ विंग, खनिजा भवन, नं. 49, रेसकोर्स रोड, बेंगलुरु 560 001, को भेजे जा सकते हैं। सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.12.2025 है। चूंकि ये रिक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जानी है, अतः गैर-सरकारी अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए या अपूर्ण पाए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट http://uidai.gov.in/image/VC_153_2025.pdf पर उपलब्ध हैं।

निदेशक (माननीय सं.)

आधार नामांकन और अपडेट सेवा अब आधार सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है।
नज़दीकी केंद्रों की जानकारी के लिए uidai.gov.in पर जाएं या 1947 पर कॉल करें।

सीबीसी54103/11/0108/2526

आरयूएचएस में दूर होगी मानव संसाधन की कमी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। रोगियों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं सुगमता एवं सुलभता के साथ उपलब्ध करवाने तथा सवाई मानसिंह अस्पताल का मरीज भार कम करने के लिए आरयूएचएस अस्पताल में मानव संसाधन की कमी दूर की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के विस्तार की दिशा में कार्डियो, न्यूरो, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए डेडीकेटेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जल्द प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही, यहां उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि रोगियों को शहर में उपचार के लिए एक और बेहतर विकल्प मिले।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को आरयूएचएस अस्पताल के निरीक्षण के उपरांत उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में आउटडोर एवं इनडोर में रोगियों की संख्या बढ़ाने तथा उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग करने के लिए एक्शन प्लान जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में निर्धारित ड्यूटी के अनुसार चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ पूरे समय उपस्थित रहें। उन्होंने इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यकतानुसार सीनियर रेजीडेंट की सेवाएं ली जाएं।

उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कक्षाओं के नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसे चिकित्सा शिक्षा की दिशा में एक उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित कर रही है, इसलिए यहां शोध, अनुसंधान एवं शिक्षण कार्यों का स्तर और बेहतर बनाया जाए।

इससे पहले प्रमुख शासन सचिव ने अस्पताल परिसर में जांच, दवा एवं उपचार व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आउटडोर, आपातकालीन इकाई, आईसीयू एवं सामान्य वार्ड सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के काउंटर एवं रोगी पंजीकरण केंद्र पर जाकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही, निर्देश दिए कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में पात्र रोगियों को इनका पूरा लाभ दिया जाए। किसी भी रोगी को योजना का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पूरी संवेदनशीलता के साथ उपचार उपलब्ध करवाया जाए।

बैठक में आरयूएचएस के कुलपति श्री प्रमोद येवले, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री ललित कुमार, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री नरेश गोयल, आरयूएचएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. महेश मंगल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बम की धमकी के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर की तलाशी ली गई, कुछ संदिग्ध नहीं मिला

जयपुर। जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में बम रखने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद शुक्रवार सुबह परिसर को खाली करवा लिया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने विस्तृत तलाशी ली, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अदालत के रजिस्ट्रार की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सभी विधिक कार्य रोक दिए गए और परिसर को तुरंत खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में वाहनों और लोगों की भी जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) ललित शर्मा ने बताया कि धमकी मिलने पर पुलिस को अलर्ट किया गया और कई टीम मौके पर भेजी गईं। उन्होंने कहा, ''अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।'' अधिकारियों ने बताया कि पूरी तलाशी के बाद परिसर में प्रवेश दोपहर दो बजे बहाल कर दिया गया।

कृषि शिक्षा का उद्देश्य खेती को विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जोड़कर किसान और राष्ट्र-दोनों को मजबूत करना है : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति, परिणामोन्मुख अनुसंधान, कृषि तकनीकी नवाचार, परीक्षा प्रणाली, सामुदायिक सेवाएँ तथा छात्र कल्याण से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की।

राज्यपाल बागड़े ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की सफलता तभी सार्थक होगी जब यहाँ अर्जित विकसित ज्ञान, शोध और नवाचार सीधे खेतखलिहान तथा किसान तक पहुँचें। उन्होंने कृषि शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, परिणामोन्मुख और स्थानीय कृषि आवश्यकताओं से जुड़ा बनाने पर बल दिया। राज्यपाल ने जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जलसंरक्षण आधारित कृषि तथा स्थानीय फसल प्रजातियों के संवर्धन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने नियमित ऑडिट व्यवस्था सुदृढ़ करने, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए पृथक व्यायामशाला, खेल मैदान, स्विमिंग पूल और छात्रावासों में स्वच्छता व पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण को विश्वविद्यालय की विशेष पहचान बनाने की सलाह भी दी।

कुलगुरु डॉ. विरेन्द्र सिंह जैतावत ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रवेश की स्थिति, परीक्षा सुधार, शोध परियोजनाओं, सामुदायिक गतिविधियों और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और विश्वविद्यालय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से भी राज्यपाल को अवगत कराया। समीक्षा बैठक के पश्चात राज्यपाल बागड़े ने कृषिवानिकी परियोजना प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। परियोजना अधिकारी डॉ. कृष्णा साहरण ने जैविक एवं प्राकृतिक पद्धति से विकसित किए जा रहे एकीकृत कृषिवानिकी मॉडलों की जानकारी दी। राज्यपाल ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए पपीता, केला, आम सहित अंगूर के पौधों को भी किसानों तक पहुंचाने का सुझाव दिया जिससे वे विविध फल उत्पादन के माध्यम से अधिक आय अर्जित कर सकें। राज्यपाल ने मृदा दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा मिट्टी एवं प्रकृति से प्राप्त सामग्री से निर्मित कलाकृतियों, रंगोली तथा पोस्टर्स का अवलोकन कर उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर राज्यपाल बागड़े ने विश्वविद्यालय परिसर में अशोक का पौधा रोपित किया तथा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार से पर्यावरण संरक्षण को सतत संस्थागत पहचान बनाने का आह्वान किया।

सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सैनिक कल्याण में दें योगदान : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस (7 दिसम्बर) के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से प्रतीकात्मक झण्डा (बैज) ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऑनलाइन अंशदान भी किया। इस अवसर पर शर्मा ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सशस्त्र सेनाओं के थल सैनिकों, नौ सैनिकों एवं वायु सैनिकों के सम्मान स्वरूप यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश की अखण्डता एवं एकता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता दिखाने का दिन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों के समर्पण, बलिदान और देश सेवा के प्रति साधुवाद प्रकट करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वीर सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके कल्याण के लिए सभी खुले हाथ से अपना योगदान देने का संकल्प लें।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर वीरेन्द्र सिंह राठौड़ सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे।

हम धर्मगुरु हैं, नेता नहीं, जहां बुलाएंगे वहां जाकर करेंगे गीता पाठ : धीरेन्द्र शास्त्री

जयपुर/दक्षिण भारत। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में जहां भी उन्हें बुलाया जाएगा, वे वहां गीता पाठ करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहाहम देशद्रोही थोड़े हैं। सनातन धर्म के लिए काम करने वाले हैं। भारत का हर प्रदेश हमारा है, पश्चिम बंगाल भी हमारा ही है। विपक्ष द्वारा लगाए जाने वाले इस आरोप पर कि शास्त्री केवल चुनाव वाले राज्यों में जाते हैं, उन्होंने कहाहम किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए हमारा कोई राजनीतिक विपक्ष भी नहीं है। बाकी, दृष्टि आपकी है। बाबरी विवाद पर बोलेवहीं जाकर जवाब देंगेबाबरी मस्जिद से जुड़े बंगाल के विवाद पर पूछे गए सवाल पर शास्त्री ने कहावहीं जाकर बोलेंगे, खबर आप तक आ जाएगी। मुस्कराते हुए उन्होंने कहाये राजनेताओं के काम हैं। हम धार्मिक गुरु हैं। हमसे गीता और रामायण के बारे में पूछिए।

धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार को जयपुर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कवि कुमार विश्वास भी उनके साथ नजर आए। यह विवाद नवंबर 2024 में शुरू हुआ, जब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद बाबरी नाम को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया। दिसंबर 2024 में बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में राम मंदिर निर्माण की बात की। टीएमसी विधायक कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की और कई विवादित बयान भी दिए।विवाद बढ़ता गया, यहां तक कि कबीर ने दावा किया कि निर्माण रोकने की कोशिश करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।7 दिसंबर को कोलकाता में 2000 संतों और 5 लाख लोगों के साथ गीता पाठसनातन संस्कृति संसद 7 दिसंबर 2025 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता जयंती पर सामूहिक गीता पाठ का आयोजन करने जा रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने ली देवनारायण योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को देवनारायण योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। विगत बैठकों में उठाए गए विषयों की तेजी से क्रियान्विति पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और प्रतिनिधिगण संतुष्ट नजर आए। विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कॉलेज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

गहलोत ने गत बैठक में दिए निर्देशों की प्रगति से समिति को अवगत करवाया। इस दौरान देवनारायण छात्रवृत्ति योजना-उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना-पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, देवनारायण गुरुकुल योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, देवनारायण आदर्श छात्रावास संचालन, देवनारायण आवासीय विद्यालय संचालन, देवनारायण बालक एवं बालिका महाविद्यालय संचालन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण देवनारायण योजना के अंतर्गत स्वीकृत मेडिकल मोबाइल यूनिट, योजना के अंतर्गत संचालित छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों की मरम्मत सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समिति के सुझावों और बैठक में उठाए सभी विषयों की माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग की जा रही है। निदेशक आशीष मोदी ने योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में आए सुझावों के आधार पर योजनाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। आगे भी निरंतर फीडबैक लेकर सुधार किया जाएगा।

प्रदेश के बड़े अस्पतालों में जयपुरिया अस्पताल की तर्ज पर होगा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम : गायत्री राठौड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में रोगियों को सुगम, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुरिया अस्पताल की तर्ज पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एवं हेल्प डेस्क व्यवस्था शुरू की जाएगी, ताकि रोगियों को कतारों से मुक्ति मिले और उन्हें इलाज के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर चक्कर नहीं काटने पड़ें। उनकी सहायता के लिए अस्पतालों में एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा, जो पूरी संवेदनशीलता के साथ रोगियों की मदद करेगा।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को जयपुरिया अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में दिशानिर्देश दिए। उन्होंने जयपुरिया अस्पताल के निरीक्षण के दौरान क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एवं हेल्प डेस्क व्यवस्था का

गहन निरीक्षण किया और पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने इन दोनों नवाचारों के लिए प्रसन्नता व्यक्त की और अन्य अस्पतालों में भी यह मैकेनिज्म अपनाने पर बल दिया।

श्रीमती राठौड़ ने जयपुरिया अस्पताल में सुविधाओं के विकास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी बड़े अस्पताल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टेण्डर्ड को पूरा करें और एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि बड़े अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं के उच्चतम मानकों को पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने अस्पताल परिसर में रोगियों एवं परिजनों के फीडबैक के लिए सुझाव पेटिका स्थापित करने तथा क्यूआर कोड सिस्टम लागू करने के भी निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अस्पताल में न्यूरो एवं कार्डियक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगी भार कम हो। उन्होंने इसके लिए जरूरी मानव संसाधन का प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में आपातकालीन इकाई एवं ट्रोमा सेंटर के विकास एवं वहां उपलब्ध सुविधाओं पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी, इनडोर, ब्लड बैंक, आपातकालीन इकाई, दवा काउंटर, जांच लैब सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया।

उन्होंने अस्पताल में साफसफाई एवं रोगी केन्द्रित सेवाओं के लिए अस्पताल प्रशासन की प्रशंसा की। श्रीमती राठौड़ ने इस दौरान रोगियों से भी संवाद किया और उनसे चिकित्सा सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। रोगियों ने कहा कि अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट व्यवस्था प्रारंभ होने से अब उन्हें कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ता। साथ ही, पारदर्शी तरीके से उपचार मिलता है।

एक रोगी ने कहा कि जयपुरिया अस्पताल में साफसफाई एवं अन्य सुविधाएं निजी अस्पताल की तरह मिल रही हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. महेश मंगल ने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एवं हेल्प डेस्क व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में हर प्रमुख विभाग एवं स्थान पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है, ताकि रोगी को संबंधित विभाग में उपचार, जांच एवं दवा आदि प्राप्त करने की जानकारी एवं जरूरी सहायता वहीं मिल सके। रोगी को अनावश्यक रूप से अस्पताल में भटकना नहीं पड़े। ये हेल्प डेस्क काउंटर जनसहयोग के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण का केंद्र बने : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शैक्षणिक प्रगति, परीक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, अनुसंधान संस्कृति तथा खेलसांस्कृतिक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालय को राष्ट्र निर्माण का वैचारिक केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अध्ययनअनुसंधान को बढ़ावा देने तथा प्रति माह प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ज्ञानसहभागिता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, कला, नेतृत्व कौशल और व्यावहारिक ज्ञान को शिक्षा का अनिवार्य घटक बनाने पर बल दिया।

उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में खेल मैदान, खेल उपकरण, कला एवं सहपाठ्यक्रम गतिविधियों के उन्नयन तथा आधुनिक खेल सुविधाएँ विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वैश्विक अनुभव के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय अकादमिक कार्यक्रमों एवं शोध गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता दोहराई।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व में किये गए 363 खेजड़ी पौधों के सामूहिक वृक्षारोपण के स्थल का पुनः अवलोकन किया और पौधों की संरक्षण व्यवस्था और उनकी वृद्धि की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल कार्यक्रम न होकर उत्तरदायित्व और निरंतर देखभाल है, इसलिए प्रत्येक पौधे को पूर्ण विकसित वृक्ष बनाने के संकल्प के साथ संरक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

विश्व मृदा दिवसः

ओडिशा के उपमुख्यमंत्री ने दिया जैविक खेती अपनाने पर जोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के उपमुख्यमंत्री के.वी. सिंह देव ने किसानों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों से भविष्य की पीढ़ियों के लिए मिट्टी उर्वरता को संरक्षित करने के वास्ते जैविक तथा पर्यावरण-अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाने की शुक्रवार को अपील की।

इस वर्ष विश्व मृदा दिवस 'हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी सिटीज' थीम पर मनाया जा रहा है। सिंह देव ने इस अवसर पर यहां आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पोषक तत्वों से पूर्ण मृदा कृषि की जीवन रेखा के साथ ही खाद्य सुरक्षा की नींव और सतत विकास का आधार है।

उपमुख्यमंत्री के साथ ही कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह देव ने कहा, ''मैं किसानों, वैज्ञानिकों और अन्य संबंधित लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मृदा की उर्वरता को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के मकसद से रासायनिक सामग्री के उपयोग कम करें, जैविक कृषि को बढ़ावा दें।'' उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम इस बात पर केंद्रित है कि खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जन और बढ़ते शहरीकरण में बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने में पोषक तत्वों से पूर्ण मृदा किस तरह अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मुझे इस महत्वपूर्ण संसाधन के संरक्षण की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की पुष्टि करने में किसानों और नीति निर्माताओं के साथ शामिल होने का सौभाग्य मिला।''

इस अवसर कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव अरबिंद पाढ़ी ने राज्य भर में मृदा परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मृदा हमारे जीवन की आधारशिला है और वह अक्षय शक्ति है जो पृथ्वी पर जीवन के प्रवाह और निरंतरता को बनाए रखती है। हमारा भोजन, पानी और पर्यावरण संतुलन सभी इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करते हैं।

कांग्रेस ने ओडिशा में एएनएम परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक की शिकायत की, राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द की

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा में विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि 'ऑक्जिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी' (एएनएम) परीक्षा आयोजित किए जाने से तीन घंटे पहले इसका प्रश्नपत्र लीक हो गया। पार्टी विधायक सी.एस. राजेन एक्का ने सदन में बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए यह आरोप लगाया। एक्का ने सदन में कहा, ''हमारे संज्ञान में आया है कि एएनएम की दोपहर दो बजे होने वाली लिखित परीक्षा से पहले इसका प्रश्नपत्र अपरा 11 बजे लीक हो गया।'' एक्का ने कहा कि मलकानगिरी और बोलंगीर जिलों में प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक हुआ तथा यहां द्वितीय वर्ष के छात्र परीक्षा देने वाले थे। इस घटना से अभ्यर्थियों और अभिभावकों में व्यापक रोष फैल गया तथा उन्होंने अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। इसके तुरंत बाद, राज्य के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशक (डीएमईटी) प्रोफेसर संतोष मिश्रा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि परीक्षा रद्द कर दी गई है।

पुतिन के सम्मान में आयोजित भोज में खरगे, राहुल को आमंत्रित नहीं किया गया : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजकीय भोज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को आमंत्रित नहीं किया गया है। मुख्य विपक्षी दल के दावे पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले को लेकर उन पर कटाक्ष किया और कहा कि 'हम होते तो अंतरात्मा की आवाज' सुनते।' उनका यह भी कहना था कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले सवालों के घेरे में आते हैं।

खेड़ा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, '' दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह हैरानी की बात है, लेकिन इस सरकार में इससे हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सरकार सभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए जानी जाती है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है।

थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर खेड़ा ने कहा, ''आप उनसे पूछिए। हम होते तो अपनी अंतररात्मा की आवाज जरूर सुनते। जिस तरह से यह आमंत्रण दिया गया है वो सवालों के घेरे में आता है और जो निमंत्रण को स्वीकार कर रहा है वो भी सवाल के घेरे में आता है।'' इससे पहले, थरूर ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख के तौर पर इस भोज के लिए आमंत्रित किया गया है और वह इसमें जाएंगे।

नीतीश कुमार ने बिहार में तीन नए विभाग बनाने की घोषणा की

पटना/भाषा। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कराने के खातिर तीन नए विभाग, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय (एमएसएमई) और राज्य विपणन प्रोत्साहन निगम के गठन की शुक्रवार को घोषणा की। एक अधिकारी के अनुसार, नव निर्मित विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन हैं।

बिहार की जीविका दीदी दूसरे राज्यों में दे रहीं प्रशिक्षण : श्रवण कुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि आज राज्य की जीविका दीदी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, असम और राजस्थान जैसे राज्यों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं जो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

वह विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे थे।

मंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू की है, जिसका क्रियान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को उसकी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है और रोजगार शुरू करने के बाद महिलाओं को आवश्यकता अनुसार दो लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कुमार ने कहा कि इस योजना से महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ ही परिवार की आय बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा, ''महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहर तक हाट-बाजार विकसित किए जा रहे हैं। अब तक 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10 हजार रुपए की सहायता दी जा चुकी है।''

कुमार ने कहा, ''आज बिहार की जीविका दीदी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, असम और राजस्थान जैसे राज्यों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। लखपति दीदी पहल के तहत जीविका ने विभिन्न स्थायी जीविकोपार्जन गतिविधियों में महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और वर्तमान में 31 लाख 71 हजार जीविका दीदियों को लखपति घोषित किया जा चुका है।''

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि विश्व बैंक के 2016 के अध्ययन के अनुसार परियोजना के प्रभाव से परिवारों की आय में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वार्षिक आय 35,968 रुपए से बढ़कर 46,758 रुपए हो गई और परिवारों का कर्ज 50 प्रतिशत से घटकर सात प्रतिशत रह गया।

मंत्री ने कहा कि 2006 में मात्र छह प्रखंडों से शुरू हुए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या आज ग्रामीण क्षेत्र में 11.03 लाख और शहरी क्षेत्र में 41,477 हो गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 45,064 नए समूहों का गठन किया गया है ऐसे में कुल 1.40 करोड़ से अधिक परिवार एसएचजी से जुड़े हैं।

पिछले 16 महीनों में दो सरकारी कॉलेजों से रैगिंग की आठ शिकायतें

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग को पिछले 16 महीनों में दो सरकारी कॉलेजों से रैगिंग की आठ शिकायतें मिली हैं। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। सूरज ने कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता राम चंद्र कदम के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि भुवनेश्वर स्थित बक्सी जगबंधु बिद्याधर (बीजेबी) स्वायत्त महाविद्यालय से चार और राउरकेला स्थित सरकारी स्वायत्त कॉलेज से चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि बीजेबी स्वायत्त कॉलेज की शिकायतों का 'दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान' कर लिया गया जबकि राउरकेला संस्थान की शिकायतों का 'एंटी-रैगिंग सेल' के निर्णय के अनुसार आरोपी विद्यार्थियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के बाद निपटारा कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि 'एंटी-रैगिंग सेल' सतर्क है और ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए त्वरित कार्रवाई कर रहा है। सूरज ने सदन को बताया कि उच्च शिक्षा विभाग राज्य भर के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की घटनाओं के संबंध में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया में है।

एसआईआर का आंकड़ा प्रकाशित करें, बीएलओ पर जानलेवा दबाव न डाला जाए : अखिलेश यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अब तक हुए काम को प्रकाशित करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर 'जानलेवा दबाव' न डाला जाए।

यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में मांग की कि राज्य में एसआईआर का जितना भी काम हुआ है, उसका आंकड़ा प्रकाशित किया जाए। उन्होंने कहा, ''बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समयावधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए।''

यादव ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उनके संगी-साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं हैं और न आगे कभी होंगे।

सपा प्रमुख ने मांग की, ''इस बात की पक्की जांच-पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज के कितने लोगों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है, हर हाल में इसे होने से रोका जाए।''

सपा प्रमुख के पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि एसआईआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य 99.89 प्रतिशत तथा डिजिटाइजेशन का कार्य 91.63 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिदिन बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है।

पोस्ट में उन्होंने कहा, ''कार्य में बीएलओ के सहयोग के लिए अतिरिक्त कार्मिक लगाये गये हैं। यह एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसके लिए आम जनता तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपील की गई है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्रत्येक बूथ पर अपना बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया।'' उन्होंने कहा, ''एसआईआर के अन्तर्गत बीएलओ को सहयोग प्रदान करने के लिए अभी तक भाजपा (भारतीय जनता पार्टी), सपा, कांग्रेस, बसपा(बहुजन समाज पार्टी), आप (आम आदमी पार्टी), माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) तथा अपना दल (एस) द्वारा अपने बीएलए नियुक्त किये गये हैं।''

ओडीओपी 2.0 के माध्यम से स्थानीय उद्योग, स्वरोजगार और निर्यात को नई ऊंचाई देने को तैयार : योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी 'एक जनपदएक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना अब अपने अगले चरण 'ओडीओपी 2.0' के माध्यम से स्थानीय उद्योग, स्वरोजगार और निर्यात को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है।

एक बयान के मुताबिक, यहां इस संबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद की विशिष्ट खाद्य परंपरा को एक संगठित पहचान देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओडीओपी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी अलग-अलग विशिष्ट खाद्य परंपराएं हैं-कहीं हलवा प्रसिद्ध है तो कहीं दालमोठ। उन्होंने निर्देश दिया कि हर जिले के विशेष

व्यंजनों की पहचान कर उनकी गुणवत्ता, स्वच्छता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडीओपी और 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) मिलकर उत्तर प्रदेश को 'लोकल से ग्लोबल' की दिशा में नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक बाजार, आधुनिक मांग, तकनीकी उन्नयन और बेहतर पैकेजिंग की आवश्यकताओं को देखते हुए ओडीओपी को और अधिक व्यापक, व्यावसायिक और परिणामोन्मुखी स्वरूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''ओडीओपी 2.0 के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद बड़े बाजार, निर्यात और स्थायी रोजगार का मजबूत आधार बनें।''

बैठक में यह भी बताया गया कि 2018 में शुरू हुई ओडीओपी योजना आज उत्तर प्रदेश के निर्यात और स्थानीय उद्योगों की रीढ़ बन चुकी है। अब तक 1.25 लाख से अधिक 'टूलकिट' वितरित किए जा चुके हैं, 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है और 8,000 से अधिक उद्यमियों को प्रत्यक्ष विपणन सहायता दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडीओपी 2.0 अब केवल एक योजना नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, स्थानीय उद्यम और निर्यात को नई ऊंचाई देने का सशक्त माध्यम बने। उन्होंने कहा कि पहले चरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों और उद्यमियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे अपने व्यवसाय का और विस्तार कर सकें।

उन्होंने निर्देश दिया, ''ओडीओपी उत्पादों को केवल पारंपरिक बाजारों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें बड़े रिटेल नेटवर्क और आधुनिक बाजारों से जोड़ा जाए। साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित हो रहे यूनिटी मॉल में ओडीओपी के समर्पित केंद्र बनाए जाएं। सभी प्रमुख रिटेल नेटवर्क से संवाद कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां उत्तर प्रदेश के उत्पाद प्रमुख रूप से प्रदर्शित हों।

वाशिंगटन की टीम में भूमिका को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए : अश्विन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन को वाशिंगटन सुंदर की टीम में भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह ऑलराउंडर इसी गफलत में रहेगा कि आखिर उसकी भूमिका क्या है।

अश्विन ने कहा कि वाशिंगटन को गेंदबाज़ी ऑलराउंडर माना जाना चाहिए और उन्हें पूरे ओवर दिए जाने चाहिए जिससे बल्लेबाजी में भी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में केवल सात ओवर फेंके और अभी तक उन्हें एक भी विकेट नहीं

मिला है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''एक बार जब आपने वाशिंगटन सुंदर को अंतिम एकादश में रखने का फैसला कर लिया, तो आपको उनकी भूमिका एक गेंदबाज के रूप में देखनी होगी जो बल्लेबाजी भी कर सकता है। आपको उन्हें उनके कोटे के सारे ओवर करवाने होंगे।''

उन्होंने कहा, ''लगातार गेंदबाजी करने पर ही उनकी (वाशिंगटन) मानसिकता एक ऐसे गेंदबाज की होगी जो बल्लेबाजी भी कर सकता है। अगर वह सिर्फ बल्लेबाजी और कुछ ओवर गेंदबाजी करेगा तो वह यही सोचता रहेगा कि आखिर टीम में उसकी भूमिका क्या है। उसे इस स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए और टीम को उसकी उचित भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए।''

भारत दूसरे वनडे में 358 रन का बचाव करने में नाकाम रहा और दक्षिण अफ्रीका ने चार विकेट से जीत के साथ तीन मैचों की श्रृंखला बराबर कर ली। पहले वनडे में भारत ने 348 रन बनाए थे और यह मैच 17 रन से जीता था।

अश्विन का मानना है कि हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में भारतीय टीम को एक अदद फिनिशर की कमी खल रही है।

शेफाली आईसीसी की महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/भाषा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में 87 रन की तेजतर्रार पारी खेलने और दो महत्वपूर्ण विकेट लेने वाली भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को नवंबर महीने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।

सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के चोटिल हो जाने के कारण शेफाली को भारतीय टीम में जगह मिली थी। उन्हें फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था और अब वह महिलाओं के पुरस्कार के लिए नामांकित की गई तीन खिलाड़ियों में शामिल हैं।

महिला वर्ग का पुरस्कार हासिल करने के लिए उन्हें संयुक्त अरब अमीरात की ईशा ओझा और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों ने बैंकॉक में पहली आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था।

यूएई की कप्तान ओझा ने सात टी-20 मैचों में 137.50 की स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए और सात विकेट लिए। उन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था। पुथावोंग 15 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं। उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ फाइनल में चार विकेट लेकर थाईलैंड को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। है।

पुरुष वर्ग में दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर, बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम और पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को नामांकित किया गया है।

केकेआर के लिए 'एक्स फैक्टर' हो सकते हैं उमरान : सुनील नारायण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/भाषा। स्टार स्पिनर सुनील नारायण ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सत्र में आंद्रे रसेल की मैदान पर पावर हिटिंग की कमी खलेगी लेकिन उन्हें लगता है कि उमरान मलिक अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई गेंदबाजी के कारण टीम के लिए 'एक्स फैक्टर' साबित हो सकते हैं।

तेज गेंदबाज उमरान कूल्हे की चोट के कारण पिछले सत्र में बाहर रहने के बाद केकेआर के लिए पदार्पण के लिए तैयार हैं और नारायण को लगता है कि जम्मू-कश्मीर के इस तेज गेंदबाज में फ्रेंचाइजी का अगला तुरुप का इक्का बनने की क्षमता है।

नारायण ने यहां पीटीआई से कहा, ''वह एक बेहतरीन गेंदबाज़ हैं। मुझे लगता है कि आईपीएल में छोटे मैदान और अच्छी पिचें होने के कारण आपको तेज़ गेंदबाज़ी के लिए एक एक्स फैक्टर की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि उमरान काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा।''

उमरान ने 18 महीने से अधिक समय तक मैदान से बाहर रहने के बाद इस घरेलू सत्र में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और जम्मू-कश्मीर के लिए सैयद मुश्ताक अली में पांच विकेट लेकर उन्होंने तुरंत ही अपनी लय पकड़ ली।

उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में उन्होंने 37 रन देकर तीन विकेट लिए और अपनी गति और तेज उछाल से केकेआर के अपने साथी रिंकू सिंह सहित अन्य बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया।

सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिलीज किए जाने के बाद उमरान को आईपीएल 2025 से पहले केकेआर ने उनके आधार मूल्य 75 लाख रुपए में अपनी टीम से जोड़ा था लेकिन चोटिल होने के कारण वह पिछले सत्र में नहीं खेल पाए थे।

केकेआर को तीन आईपीएल खिताब दिलाने वाले अहम सदस्य नारायण ने कहा, ''उम्मीद है कि वह फिट रहेंगे। मैं उन्हें 145-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदें फेंकते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं।''

रसेल ने हाल में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की और नारायण ने कहा कि टीम को उनकी कमी खलेगी।

तृणमूल सांसद ने 'बांग्लाभाषी' लोगों का मुद्दा लोकसभा में उठाया, भाजपा का पलटवार

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस की नेता शताब्दी रॉय ने देश के कुछ हिस्सों में बांग्लाभाषी लोगों को परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को लोकसभा में सरकार पर निशाना साधा, जिसे भाजपा सांसद संबित पात्रा ने असत्य बताकर खारिज कर दिया।

सदन में शून्यकाल के दौरान शताब्दी रॉय ने दावा किया कि महाराष्ट्र और कई अन्य जगहों पर बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेशी कहकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बांग्ला बोलने से कोई बांग्लादेशी कैसे हो गया? इस दौरान तृणमूल कांग्रेस और सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई।

इस बीच जब पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने भाजपा सदस्य जुगल किशोर शर्मा का नाम शून्यकाल में उनकी बात रखने के लिए पुकारा तो शताब्दी रॉय सत्तापक्ष की तरफ बढ़ गईं।

इस दौरान ऐसा लगा कि तृणमूल कांग्रेस सदस्य सत्तापक्ष की तरफ ऑन माइक से अपनी बात रखने का प्रयास करते हुए वहां पहुंची थीं।

पीठासीन सभापति ने उन्हें अपने स्थान पर लौटने के लिए कहा। सत्तापक्ष के सदस्यों ने तृणमूल सांसद के ऐसा करने पर आपत्ति जताई।

शून्यकाल में जब भाजपा सांसद पात्रा के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा, ''टीएमसी की एक सांसद ने ओडिशा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी कहकर वापस भेज रही है। यह असत्य है। ओडिशा अनादिकाल से साथ सबको साथ लेकर चलता है और बांग्ला बोलने वाले हमारे बंधु हैं।''

सुविचार

सच्चा धर्म यह है, कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है, उन्हे दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

यह बोझ भारत क्यों उठाए?

उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाकर दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है। इसके तहत कई जिलों में पुलिस और खुफिया इकाइयां गहन सत्यापन कर रही हैं। अगर अन्य राज्यों की सरकारें भी इसी तर्ज पर कार्रवाई करें तो कोई अवैध प्रवासी हमारे देश में रहने का दुस्साहस नहीं कर सकता। सरकारों के पास संसाधनों की कमी नहीं है। पुलिस और खुफिया इकाइयां बहुत आसानी से अवैध प्रवासियों का पता लगा सकती हैं। बस, इच्छाशक्ति की जरूरत है। अगर कोई सरकार मजबूती से फैसला कर ले तो नागरिक ही उसके लिए आंख-कान बन जाएंगे। वे संदिग्ध अवैध प्रवासियों की सूचना दे देंगे। अब तो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया जैसे माध्यम हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए कोई जागरूक नागरिक आसानी से सूचना दे सकता है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई हो सकती है। घुसपैठियों को बचकर भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उन तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि भारत में कानून का शासन है। यहां कोई विदेशी नागरिक अवैध तरीके से प्रवेश कर मनमर्जी से नहीं रह सकता। अगर वह अपराध करेगा तो सजा मिलेगी। धर-पकड़ की इस कार्रवाई में खुफिया इकाइयों और आम नागरिकों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लिया जाए। गांवों में तो ऐसे लोगों का पता लगाना आसान होता है, क्योंकि आबादी कम होती है। वहां ज्यादातर लोग एक-दूसरे को पहचानते हैं। बड़े शहरों में दिक्कत होती है। वहां लोग सुबह काम पर जाते हैं और रात को घर लौटते हैं। उन्हें अपने पड़ोसी के बारे में ही ज्यादा पता नहीं होता!

राज्य स्तर पर एक ऐसा फोन नंबर होना चाहिए, जिस पर कोई भी व्यक्ति अवैध प्रवासियों की सूचना दे और उसका नाम गुप्त रखा जाए। यह नंबर सोशल मीडिया पर डालने के बाद आम नागरिकों तक आसानी से पहुंच जाएगा। नागरिकों को अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए सामान्य जानकारी दी जाए।

राज्य स्तर पर एक ऐसा फोन नंबर होना चाहिए, जिस पर कोई भी व्यक्ति अवैध प्रवासियों की सूचना दे और उसका नाम गुप्त रखा जाए। यह नंबर सोशल मीडिया पर डालने के बाद आम नागरिकों तक आसानी से पहुंच जाएगा। नागरिकों को अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए सामान्य जानकारी दी जाए। उन्हें यह जरूर बताया जाए कि आपका काम सिर्फ सूचना देना है, बाकी काम सरकार का है, लिहाजा किसी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी कहां रहते हैं, किन क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें नौकरी कौन देता है, वे फर्जी दस्तावेज कहां से बनवाते हैं, वे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चीजें कहां से खरीदते हैं, किन इलाकों में अचानक अनजान चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कहां झुग्गियां खड़ी की जा रही हैं – इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जाए। किराएदारों का सत्यापन जरूर होना चाहिए। पूर्व में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ ठेकेदार अवैध प्रवासियों से मजदूर के तौर पर काम करवाते हैं। इस तरह वे स्थानीय मजदूरों का हक मारते हैं। जहां कहीं ऐसे इलाके हों, वहां सत्यापन होना चाहिए। भारतीय नागरिकों को ही काम मिलना चाहिए। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने भी चिंता जताते हुए सख्त टिप्पणी की है– 'क्या घुसपैठियों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाना चाहिए?' इस सवाल का जवाब उन कथित बुद्धिजीवियों के पास नहीं है, जो रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग करते हुए न्यायालय का द्वार खटखटा देते हैं। भारत में करोड़ों लोग बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में देश के संसाधन उन पर खर्च होने चाहिएं या घुसपैठियों के आराम का ध्यान रखना चाहिए? सरकारें सख्ती बरतें और तमाम घुसपैठियों को उनके मुल्क का रास्ता दिखाएं। अब भारत उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता।

ट्वीटर टॉक

देश में सिविल एविएशन सेक्टर इस वक्त पैरालिसिस जैसी स्थिति में आ गया है। पूरे देश में हवाई यात्री परेशान हैं और बेबस महसूस कर रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो कहीं बच्चे भूखे और थके हुए हैं, महिलाएं, वृद्ध, बीमार लोग लाचार महसूस कर रहे हैं।

–अशोक गहलोत

आज गंग नहर शताब्दी समारोह में किसान भाई-बहनों को संबोधित किया। गंग नहर के जनक महाराजा श्री गंगा सिंह जी को नमन करते हुए, उनके जनसेवा और दूरदर्शी नेतृत्व को स्मरण किया। एक सदी से यह नहर प्रदेश को हरियाली, समृद्धि और नई संभावनाएँ प्रदान कर रही है।

–भजनलाल शर्मा

झुंझुनू, राजस्थान के सपूत, 322 ए.डी. रेजीमेंट के वीर नायक विरेन्द्र सिंह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें और अथाह दुख की इस घड़ी में शोक-संतप्त परिजनों को धैर्य और संबल प्रदान करें।

–राज्यवर्धन सिंह राठौड़

प्रेरक प्रसंग

अस्वीकृति से उड़ान

सन 2009 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्रायन एक्टन ने फेसबुक और ट्विटर में नौकरी के लिए आवेदन किया। दोनों कंपनियों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा 'फेसबुक ने मुझे ठुकरा दिया, यह एक शानदार अवसर था, लेकिन शायद आगे कुछ और बेहतर मेरा इंतजार कर रहा है।' इस अस्वीकृति ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक नई राह पर प्रेरित किया। उन्होंने अपने मित्र जेन कौम के साथ मिलकर एक नया एप शुरु किया एक सरल, विज्ञापन-मुक्त मैसेजिंग सेवा, जिसका नाम था व्हाट्सएप। कुछ ही वर्षों में व्हाट्सएप दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप बन गया। वर्ष 2014 में उसी फेसबुक ने जिसे ब्रायन ने आवेदन दिया था, इस एप को 19 अरब डॉलर में खरीद लिया। तकनीकी इतिहास की सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक। ब्रायन एक्टन का यह सफर दर्शाता है कि अस्वीकृति अंत नहीं होती; वह अक्सर एक नई शुरुआत का संकेत होती है।

सामयिक

संचार साथी ऐप: अपेक्षा है निजता बनाम सुरक्षा के बीच संतुलन की

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक विचित्र प्रवृत्ति विकसित होती दिख रही है, जहाँ सत्ता द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को विपक्ष संदेह की दृष्टि से देखता है। संचार साथी ऐप को लेकर इन दिनों इसी प्रकार का विवाद एवं विरोध का वातावरण बना हुआ है। केंद्र सरकार की यह सोच कि हर नए स्मार्टफोन में इस ऐप को अनिवार्य किया जाए, विपक्ष ने इसे निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए कठोर शब्दों में चुनौती दी और संसद के शीतकालीन सत्र में इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और इससे व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढने की आशंकाएं व्यक्त की है। विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण व नागरिकों की निगरानी करने वाला टूल बताया। इस बहस के बीच विपक्ष को नया मुद्दा मिलते देख केंद्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर ऐप प्री-इंस्टॉल करने का अपना फैसला वापस ले लिया। सरकार ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल इसे स्वैच्छिक बना दिया है अर्थात जो चाहे ऐप को रखे, जो चाहे उसे हटाए। परंतु इस विवाद ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया है कि क्या हम केवल विरोध की राजनीति में वास्तविक चुनौतियों और आवश्यकताओं को भुला रहे हैं?

वास्तविकता यह है कि डिजिटल युग आज अवसरों के साथ-साथ अभूतपूर्व संकटों का भी युग है। साइबर अपराध, चोरी, जासूसी, डेटा हेरफेर, गलत सूचना, आतंकवादी नेटवर्किंग-इन सबने सुरक्षा की चुनौतियों का नया स्वरूप निर्मित किया है। संयुक्त राष्ट्र तक यह स्वीकार कर चुका है कि अगला विश्वयुद्ध यदि हुआ, तो वह साइबर मोर्चे पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे समय में क्या किसी राष्ट्र की सरकार को निष्क्रिय खड़ा रहना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। इसलिए संचार साथी ऐप मात्र निगरानी का यंत्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक संरक्षण एवं डिजिटल अपराध नियंत्रण की रणनीतिक आवश्यकता के रूप में उभरा है। सरकार का सही कहना था कि डिजिटल होती दुनिया में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई थी। उसका कहना था कि लगातार जटिल होते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी पहल अपरिहार्य है।

विपक्ष का विरोध इसलिए भी एकांगी है क्योंकि केवल यह निजता के सवाल पर केंद्रित है। परंतु निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित, पूर्ण स्वतंत्र नहीं, बल्कि परिस्थितिनिष्ठ है। लोकतंत्र व्यक्ति को अधिकार देता है, साथ ही साझा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मांगता है। जब डिजिटल मंचों पर राष्ट्रीय अखंडता, आर्थिक व्यवस्था, सामरिक रहस्य और सामाजिक शांति पर संकट मंडराते हों, तो सरकार को हस्तक्षेप करना नैतिक रूप से उचित ही नहीं, बल्कि आवश्यक हो जाता है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन-सभी देशों के पास निगरानी आधारित साइबर सुरक्षा प्रणालियाँ हैं। क्या उनकी लोकतांत्रिक संरचनाएँ इस कारण क्षीण हो गईं? नहीं, क्योंकि निगरानी और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया गया। भारत को भी इसी संतुलन की आवश्यकता है। यह सही है कि किसी भी डिजिटल ऐप में निगरानी का वहनीय स्वरूप रखना चाहिए, जिससे नागरिक की व्यक्तिगत जिंदगी पर अनावश्यक हस्तक्षेप न हो। सरकार ने भी यही स्पष्ट किया है कि संचार साथी नागरिक के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहता, बल्कि उसे साइबर अपराध, हैकिंग, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, एवं डिजिटल आतंकवाद से बचाने हेतु काम करेगा। विडंबना यह है कि विपक्ष इस ऐप को 'निष्ठा परीक्षण', 'मनोवैज्ञानिक निगरानी' और 'गोपनीयता हनन' का उपकरण बताकर भय पैदा कर रहा है, जबकि पूर्व में स्वयं उनकी सरकारें समान तंत्र विकसित कर चुकी हैं, चाहे वह आधार डेटा सुरक्षा हो, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हों या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के निगरानी प्रोटोकॉल।

सवाल यह है कि यदि अपराधी, आतंकवादी, अलगाववादी, साइबर गैंग्स संगठित डिजिटल हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या सामान्य नागरिकों को असुरक्षित छोड़ दिया जाए? क्या यह लोकतंत्र का तकाज़ा है कि सरकार देखती रहे और समाज अपराध की प्रयोगशाला बन जाए? वास्तव में यह संकट केवल भारत का नहीं, विश्व का है। आज की दुनिया में जो राष्ट्र डिजिटल नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं करता, उसकी सुरक्षा दीवारें कागज़ की नाव जैसी सिद्ध होती हैं। इसलिए यह कहना कि संचार साथी ऐप अनावश्यक या दमनकारी है, वस्तुस्थिति से आंखें मूंद लेने जैसा है। निश्चित रूप से एक सवाल उठता है, क्या ऐप डेटा सुरक्षा की गारंटी देगा? यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार को इस ऐप के उद्देश्य और डाटा संचालन नीति को पारदर्शी रूप में सार्वजनिक करना चाहिए। यदि इस पर स्वतंत्र ऑडिट हो, निजता सुरक्षा प्रावधान हों, दुरुपयोग को रोकने वाली न्यायिक निगरानी हो तो विरोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। परंतु विपक्ष का विरोध नीतिगत सुधारों की दिशा में न होकर केवल राजनीतिक अवसरवाद प्रतीत होता है। यह भी सही है कि नागरिकों की चिंताएँ निराधार नहीं, भारत में डेटा सुरक्षा कानून अभी भी परिपक्व नहीं है, डिजिटल संरचनाएँ जवाबदेही की दृष्टि से मजबूत नहीं हैं। अतः संचार साथी के विकास के साथ-साथ देश में निजता सुरक्षा कानूनों को और अधिक कठोर, दंडात्मक एवं न्यायिक रूप से संरक्षित बनाने की आवश्यकता है।

यदि इस ऐप के कार्यों पर दृष्टि डालें तो उसके पीछे सोच यह है कि मोबाइल संचार के माध्यम से होने वाले अपराधों की पहचान, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग को व्यवस्थित किया जा सके। यह व्यक्ति की निगरानी का उपकरण कम और अपराध नियंत्रण की प्रणाली अधिक है। भारत में साइबर अपराधों में प्रति वर्ष 63 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जा रही है, लाखों लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार बन रहे हैं, बैंकिंग ठगी से लेकर सोशल मीडिया मनोवैज्ञानिक अपराधों तक का दायरा बढ़ रहा है। क्या सरकार की चुप्पी इन अपराधियों को खुला मैदान नहीं दे देती? इसलिए संचार साथी जैसे कदमों का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा का विस्तार है, न कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का संकुचन।

यदि इस ऐप के कार्यों पर ष्टि डालें तो उसके पीछे सोच यह है कि मोबाइल संचार के माध्यम से होने वाले अपराधों की पहचान, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग को व्यवस्थित किया जा सके। यह व्यक्ति की निगरानी का उपकरण कम और अपराध नियंत्रण की प्रणाली अधिक है। भारत में साइबर अपराधों में प्रति वर्ष 63 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जा रही है, लाखों लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार बन रहे हैं, बैंकिंग ठगी से लेकर सोशल मीडिया मनोवैज्ञानिक अपराधों तक का दायरा बढ़ रहा है।

कठोर सत्य यह है कि राष्ट्र केवल अधिकारों पर आधारित नहीं होते, जिम्मेदारियों और सुरक्षा तंत्रों पर भी टिके होते हैं। एक नागरिक के रूप में हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित हो, हमारा पैसा सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित हो परंतु जब सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाए, तो हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। यह राजनीतिक अधिक है, जहाँ हम एक विश्वव्यापी सिद्धांत को भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ ही टिक सकती है। इसलिए संचार साथी ऐप पर संतुलित दृष्टि ही सार्थक है। सरकार को उसकी संरचना पारदर्शी, उत्तरदायी और कानून नियंत्रित रखनी चाहिए, और विपक्ष को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि डिजिटल भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ केवल नारे से हल नहीं होंगी, बल्कि तकनीकी सुरक्षा तंत्रों से ही नियंत्रण संभव होगा। लोकतंत्र में आलोचना आवश्यक है, परंतु रचनात्मक आलोचना, जिसमें सुधार की मांग होती है, न कि केवल अस्वीकरण। यदि राजनीतिक वर्ग इस बहस को इसी दिशा में ले जाए, तो संचार साथी ऐप न केवल विवादित विषय रहेगा बल्कि डिजिटल सुरक्षा के लिए नागरिक-हितकारी उपकरण के रूप में स्थापित भी होगा।

निस्संदेह, आज के डिजिटल युग में व्यक्ति का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। जिसकी हर कीमत पर सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं इसके साथ ही इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं कुछ अन्य ऐप हमारे डेटा में तो सेंध नहीं लगा रहे हैं? सरकार को इससे उपभोक्ता की सुरक्षा करनी होगी। वहीं तर्क दिया जा रहा है कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के बजाय आम लोगों को नई तकनीक और इसके इस्तेमाल के लिये सतर्क करने को देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

साथ ही इसके लिये आम जनता को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे तकनीक के जरिये साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम को गति दी जा सके। अंततः यह समझना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता-दोनों अनिवार्य हैं। चुनौती इन्हें संतुलित करने की है, न कि किसी एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की। यदि यह संतुलन नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बने, तो संचार साथी ऐप देश के डिजिटल भविष्य की सुरक्षा का सेतु बन सकता है। विरोध की राजनीति नहीं, समझ और समाधान की राजनीति आज की आवश्यकता है, यही इस ऐप की वास्तविकता और उपयोगिता को समझने की दिशा है।

ओटीटी की अनियंत्रित अश्लीलता

नजरिया

साहित्य परिषद् और न्यायपालिका की साझा चिंता

डॉ. प्रवीण दाताराम गुगनानी

नवम्बर माह में देश के सांस्कृतिक परिदृश्य में दो ऐसी घटनाएँ सामने आईं, जिन्होंने भारतीय समाज के नैतिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक संरचना और युवा पीढ़ी के मानसिक भविष्य पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। एक ओर अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रही अश्लील और मूल्यहीन सामग्री के विरुद्ध अपनी चिंता दर्ज कराते हुए एक व्यापक प्रस्ताव पारित किया। दूसरी ओर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ओटीटी की अनियंत्रित सामग्री को लेकर सरकार को कठोर कदम उठाने की सलाह दी। दोनों घटनाएँ मिलकर एक ऐसे संकट की ओर संकेत करती हैं, जिसे अब अनदेखा करना राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। भारतीय समाज लंबे समय से अपनी सांस्कृतिक आत्मा, नैतिक मर्यादाओं और पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता रहा है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन के नाम पर इन मूल्यों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त किया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जो एक समय रचनात्मकता, स्वतंत्र प्रयोग और कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम माने जाते थे, अब बड़े स्तर पर अश्लीलता, उग्रता, विकृति और अराजकता के केंद्र बनते जा रहे हैं। फिल्मों और वेबसीरीज में नग्नता और हिंसा को 'रियलिज्म' का नाम दिया जा रहा है, पात्रों की भाषा में गालियों और भद्दे संवादों को 'क्रिएटिव फ्रीडम' बताकर परोसा जा रहा है और युवा पीढ़ी इसे आधुनिकता का प्रतीक समझने के भ्रम में फँसती जा रही है।

अखिल भारतीय साहित्य परिषद जो भारत की सभी भाषाओं, बोलियों और लिपियों के संरक्षण-संवर्धन का संवैधानिक दायित्व निभाने वाला संगठन है ने इसी संकट को रेखांकित किया है। परिषद का कहना है कि ओटीटी की सामग्री युवाओं के मन-मस्तिष्क में उग्रता, अश्लीलता, विकृत यौनाचार, नशाखोरी और हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही है। न केवल सामग्री, बल्कि उस सामग्री के प्रचार-प्रसार की शैली भी उतनी ही चिंताजनक है। पोस्टर, ट्रेलर, सोशल मीडिया रीलेसबमें आकर्षण का आधार 'संस्कृति-विरोध' और 'वर्जना-भंग' बनता जा रहा है। विभिन्न शोध भी इस संकट की पुष्टि करते हैं। हाल ही में दिल्ली और मुंबई के कॉलेजों में किए गए सर्वे से पता चला कि 14 से 18 वर्ष के बीच के 70% बच्चे बिना किसी आयु-नियंत्रण के ओटीटी पर वयस्क सामग्री देखते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक रिपोर्टें बताती हैं कि लगातार हिंसा और अश्लीलता के संपर्क में रहने से किशोरों में तनाव, अवसाद, आक्रामकता और संबंधों की गलत समझ विकसित होती है।

साहित्य परिषद ने केवल ओटीटी ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती विकृति पर भी चिंता जताई है। आज कई लोकप्रिय गेम, जिनमें हिंसा, हत्याएँ और आभासी अपराध मुख्य तत्व हैं, युवाओं में नशे की तरह फैल चुके हैं। बीते वर्षों में 'ब्लू व्हेल चैलेंज', 'पबजी' की लत से मानसिक विकृति, चोरी-डकैती और आत्महत्या तक की घटनाएँ सामने आईं। कई राज्यों में ऐसी घटनाओं के बाद गेमिंग पर प्रतिबंध और निगरानी की माँग उठी, किंतु इसका व्यापक समाधान आज भी प्रतीक्षित है। इस संदर्भ में परिषद ने जो पाँच प्रमुख माँगें रखी हैं, वे पूरी तरह तार्किक एवं राष्ट्रीय हित में हैं- स्वायत्त नियामक संस्था का गठन, सांस्कृतिक संवेदनशीलता की अनिवार्यता, बच्चों के लिए आयु-आधारित सामग्री का नियंत्रण, विकृत सामग्री पर कानूनी कार्रवाई और भारतीय मूल्यों पर आधारित वैकल्पिक मनोरंजन को प्रोत्साहन। वास्तव में, यदि एक राष्ट्र अपनी किशोर और युवा पीढ़ी को ही सुरक्षित न रख सके, तो उसकी प्रगति और सांस्कृतिक गरिमा दोनों खतरे में पड़ जाती हैं।

इसी के समानांतर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ इस मुद्दे को और गंभीर बनाती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अमूल्य अधिकार है, पर इसका दुरुपयोग समाज के लिए हानिकारक है। अदालत ने यह भी कहा कि अश्लील सामग्री देने से पहले चेतावनी और नियमन अनिवार्य होना चाहिए। न्यायालय का यह संकेत महज कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि समाज के प्रति नैतिक चेतावनी है यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह प्रवृत्ति विकृति और अराजकता का रूप ले सकती है। साहित्य परिषद ने अपने अधिवेशन में आत्मबोध से विश्वबोध की परिकल्पना को आगामी वर्षों के वैचारिक पथ के रूप में निर्धारित किया है। यह संकल्प इस बात का संकेत है कि राष्ट्र की आत्मा तभी विश्वगुरु बन सकती है जब वह पहले स्वयं के भीतर की विकृतियों को पहचाने और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। ओटीटी और डिजिटल माध्यमों की यह उच्छृंखलता भारत की सांस्कृतिक आत्मा के सामने वही चुनौती खड़ी कर रही है, जो औपनिवेशिक काल में भाषा, संस्कृति और परंपरा के सामने खड़ी हुई थीबस माध्यम बदल गए हैं, स्वरूप बदला है, संकट वही है।

आज आवश्यकता सांस्कृतिक पुनर्जागरण की है। कई देश जैसे दक्षिण कोरिया, जापान और चीनअपने डिजिटल माध्यमों पर कठोर सांस्कृतिक नियंत्रण रखते हैं। चीन में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गेमिंग खेलने के घंटे कानूनी रूप से सीमित हैं। दक्षिण कोरिया में अश्लील सामग्री का प्रसार कड़े दंड का विषय है। जापान ने मीडिया और मनोरंजन में सांस्कृतिक मूल्यों को अनिवार्य तत्व बनाया है। ये देश तकनीकी रूप से विकसित होने के बावजूद मूल्यहीनता को आधुनिकता का पर्याय नहीं मानते। भारत के लिए यह समय है कि वह अपनी सांस्कृतिक आत्मा को खोए बिना आधुनिकता की ओर बढ़े। समस्या यह भी रही है कि 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जहाँ सभी सामाजिक और परंपरागत मान्यताएँ अप्रासंगिक बताई जाएँ। यह स्वतंत्रता जब मर्यादा खो देती है, तो वह स्वेच्छाचार बन जाती है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार उतना ही पवित्र है जितना उसका दुरुपयोग खतरनाक। समाज जब तक अपनी दिशाबोध खोए बिना स्वतंत्रता की सीमाएँ तय नहीं करेगा, तब तक अश्लीलता, हिंसा और विकृति का बाजार बढ़ता ही रहेगा। आज ओटीटी की सामग्री केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाला तंत्र बन चुकी है।

जिस समाज में मनोरंजन संवेदना और मर्यादा पर भारी पड़ने लगे, वहाँ संस्कृति और भविष्य दोनों संकटग्रस्त हो जाते हैं। परिवार टूटने लगते हैं, संबंध उपभोग की वस्तु बन जाते हैं और जीवन मूल्य व्यंग्य का विषय। साहित्य परिषद और सर्वोच्च न्यायालय की संयुक्त चिंता यह स्पष्ट करती है कि यह केवल 'कंटेंट' का मुद्दा नहीं, बल्कि 'सामाजिक दिशा' का प्रश्न है। यह आज का संकट नहीं, आने वाले वर्षों की संभावित आपदा का पूर्व संकेत है। यदि समाज चाहता है कि उसकी भावी पीढ़ी संवेदनशील, मजबूत और मूल्यवान बने, तो ओटीटी के इस अनियंत्रित विस्तार को नियमन और मर्यादा की आवश्यकता है। यह केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि समाज, परिवार और शिक्षा संस्थानों की भी समान जिम्मेदारी है। भारत आत्मबोध के मार्ग पर खड़ा है। आत्मबोध तभी संभव है जब समाज अपनी मूल सांस्कृतिक चेतना को पहचानकर भविष्य की दिशा तय करे। (हि.स.)

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

लंदन में शाहरुख-काजोल की कांस्य प्रतिमा का अनावरण, अभिनेत्री ने जताई खुशी

मुंबई । बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' के रिलीज को 30 साल पूरे हो गए हैं। इस खुशी में लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर पर अभिनेता शाहरुख खान और काजोल की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे लेकर अभिनेत्री काजोल ने खुशी जाहिर की है। इस मौके पर अभिनेत्री काजोल ने फिल्म की शूटिंग के पुराने दिन याद किए। उन्होंने बताया, हम यूरोप में बस के ऊपर शूटिंग कर रहे थे और वहां बहुत ठंड थी, हल्की बारिश भी हो रही थी। बिल्कुल भी धूप नहीं थी। हम सब कांप रहे थे। हमारे स्वेटर बस के नीचे रखे थे और हम बिना स्वेटर के ऊपर शूट कर रहे थे। हमारी कोरियोग्राफर सरोज जी नहीं होती, तो वह सीन शूट करना मुश्किल ही था। पूरी फिल्म में ऐसे कई मजेदार पल थे, लेकिन हमने किसी तरह शूट कर लिया। आज जब उस सीन को याद करती हूं तो हंसी आती है। अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म को भारत समेत कई देशों में पसंद किया जाता है। उन्होंने कहा, हमारी फिल्म विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए तो घर की याद दिलाती है। यह उनके लिए एक पहचान बन गई है, जो आज भी भारत से दूर रहता है, उसे यह फिल्म देखकर अपनापन महसूस होता है।

इसी के साथ अभिनेत्री ने अपनी प्रतिमा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि लोग इसके साथ ढ़ेर सारी तस्वीरें लेंगे। मैं चाहती हूं कि हर कोई इस फिल्म को देखे और वही प्यार और अपनापन महसूस करें, जो हम महसूस करते हैं। साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' पहली भारतीय फिल्म है, जो लीसेस्टर स्क्वायर पर प्रतिमा के साथ सम्मानित की गई थी। फिल्म का निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म में काजोल और शाहरुख के अलावा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मंदिरा बेदी समते कई कलाकार मुख्य भूमिका में थे। इसकी कहानी दर्शकों के दिल में बस गई और आज भी दर्शक इसे देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म ने करीब 90 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

दस मिनट में सेवाएं देने वाले 'डिलीवरी ब्वॉय' की हालत दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर : राघव

विलंब होने पर ग्राहक डिलीवरी ब्वॉय को पहले तो फोन कर डांटता है फिर उसे यह कह कर डराता है कि तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और फिर उसे एक स्टार की रेटिंग दे कर उसकी महीने भर की मेहनत पर पानी फेर देता है। चड्ढा ने कहा कि इन लोगों का काम रोज 12 से 14 घंटे होता है, चाहे मौसम कोई भी हो।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। ऑर्डर देने के बाद दस मिनट के भीतर या यथाशीघ्र सेवाएं देने वाले 'डिलीवरी ब्वॉय (आपूर्ति करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि)' की समस्याएं उठाते हुए आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इन अनदेखे पहियों की खामोशी के पीछे रोजगार की जरूरत और उसे लेकर व्याप्त असुरक्षा इन्हें अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर करती है। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए चड्ढा ने कहा जोमैटो, स्विगी के डिलीवरी ब्वॉय, ओला एवं उबर के ड्राइवर, ब्लिंकिट एवं जैप्टो के राइडर एवं अर्बन कंपनी के प्लंबर या ब्यूटीशियन वैसे तो गिग वर्कर हैं लेकिन वास्तव में ये लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अनदेखे पहिये हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी में अहम बदलाव लाने वाली ई कॉमर्स और इन्स्टा डिलीवरी कंपनियां इन खामोश कार्यबल की बदौलत अरबों रुपये कमा चुकी हैं और कमा रही हैं लेकिन यह बदलाव लाने वाले और इन कंपनियों को अरबपति बनाने वाले कामगारों की हालत दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर है। चड्ढा ने कहा कि तेज गति और आपूर्ति समय के दबाव के चलते यह गिग वर्कर सोचता है कि अगर देर हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, प्रोत्साहन राशि कट जाएगा, ऐप लॉगआउट कर देगा या आईडी ब्लॉक कर देगा। उन्होंने कहा कि इसी डर से वह लाल बत्ती को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डालते हुए शीघ्रता से सामान की आपूर्ति करने का प्रयास करता है।

उन्होंने कहा कि आपूर्ति में दस मिनट का विलंब होने पर ग्राहक की नाराजगी का डर मन में रहता है। उन्होंने कहा कि विलंब होने पर ग्राहक डिलीवरी ब्वॉय को पहले तो फोन कर डांटता है फिर उसे यह कह कर डराता है कि तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और फिर उसे एक स्टार की रेटिंग दे कर उसकी महीने भर की मेहनत पर पानी फेर देता है। चड्ढा ने कहा कि इन लोगों का काम रोज 12 से 14 घंटे होता है, चाहे मौसम कोई भी हो। इनके पास सुरक्षा के उपकरण भी नहीं होते और इन्हें विशेष बोनस या अतिरिक्त भत्ता भी नहीं मिलता। इनके लिए कमाई कम, बीमारी ज्यादा वाली हालत है।

उन्होंने कहा इसके बावजूद अपना दर्द छिपा कर, विषम परिस्थितियों में, ऑर्डर लाने के बाद ये लोग मुस्कुरा कर कहते हैं कि धन्यवाद महोदय, कृपया पांच स्टार की रेटिंग दे दीजिये। उन्होंने कहा कि इनकी हालत फैक्टरी के दिहाड़ी कर्मचारियों से भी बदतर है क्योंकि न इनकी पक्की नौकरी होती है, न इनका कोई सुरक्षा बीमा होता है। उन्होंने कहा कि ये लोग भी किसी के बेटे, भाई, पति और पिता होते हैं और इन पर इनके परिवार आश्रित होते हैं। चड्ढा ने कहा कि सरकार को इन 'गिग वर्कर्स' की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए और कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे इन कामगारों को राहत मिल सके।

निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर 'मुस्लिम आरक्षण' का आरोप लगाया, सरकार से समिति बनाने का आग्रह किया

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस पर 'मुस्लिम आरक्षण' को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार को एक समिति बनाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के आरक्षण की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस का हाथ मुसलमानों के साथ है...उसने मुस्लिम समुदाय को पहले आंध्र प्रदेश में चार प्रतिशत आरक्षण दिया और अब वही तेलंगाना और कर्नाटक में किया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार को एक समिति बनाकर आरक्षण बचाना चाहिए।

लिनोका के अचुमी बनीं मिस नगालैंड 2025

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोहिमा। नगालैंड की राजधानी कोहिमा में मिस नगालैंड प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में लिनोका के. अचुमी ने मिस नगालैंड-2025 का खिताब जीता। हॉर्नबिल महोत्सव के जश्न के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन 'ब्यूटी एंड एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ नगालैंड' ने पर्यटन और उच्च शिक्षा विभागों के सहयोग से किया था। बृहस्पतिवार शाम हुए इस आयोजन में राज्य की प्रतिभाशाली युवा हस्तियों का उत्साहवर्धन करने के लिए भारी संख्या में दर्शक उमड़े। लिनोका ने दो अतिरिक्त पुरस्कार 'मिस मल्टीमीडिया' और 'मिस टैलेंट' जैसे पुरस्कार भी जीते जिससे वह शाम की सबसे चर्चित प्रतियोगियों में से एक बन गईं। बेंगदांगियेनला ने प्रथम उपविजेता का खिताब हासिल किया, जबकि क्रिस्टीना एच येप्थो को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया।

काशिका कपूर ने बिखेरी ओल्ड-हॉलीवुड ग्लैमर की चमक

मुंबई/एजेन्सी

कभी-कभी फैशन कपड़े और कढ़ाई से आगे बढ़कर एक कहानी बन जाता है और काशिका कपूर का यह लुक बिल्कुल वैसा ही एक पल है। काले रंग के दिलकश गाउन में, जिस पर बारीकी से की गई चांदी की कढ़ाई सितारों की तरह चमक रही थी, काशिका ने ओल्ड-हॉलीवुड की एलिगेंस और आधुनिक जादू का ऐसा मिश्रण रचा कि नज़रें ठहर जाएँ। उनका गाउन, पूरी तरह तराशा हुआ, उनके व्यक्तित्व के साथ ऐसे बहता है जैसे उनके इर्द-गिर्द रोशनी की नदी बह रही हो। हर पैटर्न, हर चमक उनके हर कदम के साथ जीवंत हो उठती है। हर तस्वीर मानो किसी सदाबहार फिल्म का स्थिर फ्रेम लगती है संजीदा, खूबसूरत और बेमिसाल शालीनता से भरा हुआ। लेकिन इस लुक की असली खूबसूरती काशिका की मौजूदगी है। वह सिर्फ गाउन नहीं पहनतीं वह उसे जीवन दे देती हैं। जब उनके हाथ नरम, बैले-सी मुद्रा में ऊपर उठते हैं और ठोड़ी हल्के-से प्रकाश की ओर झुकती है, तो पूरा माहौल एक मंच की तरह महसूस होने लगता है। उनके मुलायम कर्ल्स, नाज़ुक और सुरुचिपूर्ण ज्वेलरी, और मेकअप की हल्की, चमकती आभा सब मिलकर एक ऐसा रूप रचते हैं जो एक साथ क्लासिक भी है और खगोलीय भी। और फिर आता है सबसे दिल पिघला देने वाला पल वह तस्वीर जहाँ क्रीम-रंग के नन्हे पप्पीज़ का घेरा उन्हें ऐसे घेरे हुए है मानो वह उनकी चाँद हों। वैभव और मासूमियत का ऐसा संगम दुर्लभ है, लेकिन काशिका इसे सहजता और सादगी से निभा लेती हैं। हाई-ग्लैम गाउन और पप्पीज़ की कोमल चंचलता के बीच जो विपरीतता है, वही इस तस्वीर को आइकॉनिक बनाती है ऐसा दृश्य जो आपकी स्क्रोलिंग रुकने के बाद भी मन में बसा रहता है। काशिका हमेशा से ही अपने फैशन पलों में भावना घोल देने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन यह शूट उनकी विकसित होती पहचान का जश्न सा लगता है एक ऐसी स्टार जो जानती है कि एलीगेंस और गर्मजोशी, ग्लैमर और आत्मा के बीच परफेक्ट संतुलन कैसे रचा जाता है।

सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपना 'धड़क 2' अवॉर्ड सक्षम टेट को किया समर्पित

मुंबई/एजेन्सी

अपनी पिछली फिल्म 'धड़क 2' में निलेश का किरदार निभाकर दर्शकों के साथ अपने आलोचकों का भी दिल जीत चुके सिद्धांत चतुर्वेदी को हाल ही में इस किरदार के लिए पावर पैक्ड परफॉर्मर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग का शिकार हुए दिवंगत सक्षम टेट को समर्पित कर दिया। मंच से दिवंगत सक्षम टेट को श्रद्धांजलि देते हुए सिद्धांत ने न सिर्फ संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखी बल्कि एक सशक्त संदेश भी पेश किया।उन्होंने कहा, यह अवॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि यह उन सभी का है, जिन्हें कभी जाति के आधार पर बहिष्कृत किया गया, किनारे किया गया और भेदभाव का शिकार होना पड़ा।

हालाँकि इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ अपने खड़े होने, लड़ने और सिर्फ 'मौजूद' रहने के अधिकार को हासिल किया, बल्कि अपने लिए एक ज़मीन भी तैयार की। उनकी इसी जिजीविषा को सलाम करते हुए, मैं यह अवॉर्ड दिवंगत सक्षम टेट को समर्पित करता हूँ, जिनके पीछे उनका पूरा परिवार और पूरा गाँव हैं और आज मेरा दिल भी है। सिर्फ यही नहीं आगे बढ़कर सिद्धांत ने 'धड़क 2' की निर्देशिका शाज़िया इक़बाल को धन्यवाद दिया, जिन्होंने फ़िल्म को हर तूफ़ान से बचाया, और लेखक राहुल बडवेलकर की भी सराहना की, जिन्होंने इन हालातों में चुपचाप साँसे ले रही खामोशी को सच में बदला।

अपनी गहरी और व्यक्तिगत समर्पण के साथ, सिद्धांत चतुर्वेदी ने न सिर्फ अपने सम्मान के क्षण का उपयोग वास्तविक अन्याय की कहानियों को आवाज़ देने के लिए किया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि 'धड़क 2' जैसी कहानियाँ साहस, संवेदना और बेबाक ईमानदारी के साथ कही जाती रहनी चाहिए। सिद्धांत की आगामी फिल्मों की बात करें तो अगले वर्ष वैलेंटाइन डे के दौरान उनकी फिल्म 'दो दीवाने शहर में' 20 फरवरी को रिलीज़ होगी, जिसमें वे पहली बार मृणाल ठाकुर के साथ 90 के दशक की प्रेम कहानी दर्शकों को परोसेंगे।

पटना बुक फेयर के दौरान विज़िटर्स फोटो के लिए पोज़ देते हुए।

'मस्ती 4' को साइन करने में झिझक रही थीं एलनाज नोरौजी, कहा- 'इमेज पर गलत असर पड़ने का था डर'

मुंबई/एजेन्सी

आज के दौर में फिल्मों और वेब सीरीज में बोल्ड कंटेंट को लेकर दर्शकों की राय पहले से कहीं ज्यादा बंटी हुई है। छोटे से छोटे सीन या डायलॉग्स भी अक्सर बड़े विवाद का कारण बन जाते हैं। इसी माहौल में जब कोई कलाकार एडल्ट-कॉमेडी जैसी संवेदनशील शैली में कदम रखने का फैसला करता है, तो यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसी तरह का अनुभव अभिनेत्री एलनाज नोरौजी ने भी किया। उन्होंने 'मस्ती 4' जैसी बोल्ड कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनने से पहले काफी सोच-विचार किया था। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में एलनाज नोरौजी ने कहा, मस्ती 4 में काम करने को लेकर मैं शुरू में काफी झिझक रही थी। आज के समय में दर्शक जिस तरह से बोल्ड कॉमेडी पर प्रतिक्रिया देते हैं, उससे कलाकारों पर ज्यादा दबाव बन जाता है। मुझे डर था कि कहीं मेरी छवि पर इसका गलत असर न पड़े। लेकिन, जैसे-जैसे फिल्म की कहानी पढ़ी, मेरा नजरिया बदलता गया।

उन्होंने कहा, ''इस बार की कहानी सिर्फ पहले वाली फिल्मों की तरह चुटकुलों और मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कुछ नया, अलग और ज्यादा मनोरंजक जोड़ने की कोशिश की गई है। इस खासियत के चलते मैंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का फैसला लिया।'' उन्होंने कहा, ''इस फिल्म ने मुझे अपने अभिनय का एक अलग पहलू पर्दे पर दिखाने का मौका दिया। एक कलाकार के रूप में मैं हमेशा से चाहती हूं कि दर्शक मुझे केवल एक ही तरह के किरदारों में सीमित न देखें।

इस फिल्म में बिंदिया का रोल मेरी एक्टिंग रेंज को सामने लाने का मौका था, और इसलिए मैंने इसे स्वीकार किया।'' 'मस्ती 4' एक एडल्ट-कॉमेडी फिल्म है, जिसे मिलाप मिलन जावेरी ने निर्देशित किया है। यह मशहूर 'मस्ती' फिल्म सीरीज का चौथा भाग है। फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी पहले की तरह लीड रोल में नजर आ रहे हैं। 'मस्ती 4' सिनेमाघरों पर 21 नवंबर को रिलीज हो चुकी है।

सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने पूरे किए 5,000 एपिसोड

मुंबई/एजेन्सी

12 जनवरी 2009 से शुरू हुए सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने इतिहास रच दिया है। सीरियल ने हाल ही में अपने 5,000 एपिसोड पूरे होने का जश्न मनाया और सीरियल के निर्माता राजन शाही ने अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया। सीरियल के 5,000 एपिसोड पूरे होने की खुशी में बड़ा सेलिब्रेशन रखा गया और इस मौके पर दूसरी पीढ़ी के कार्तिक और नायरा को भी देखा गया। सीरियल के 5,000 एपिसोड पूरे होने की खुशी में पहले सेट पर भवन और पूजा हुई, जिसके बाद राजन शाही ने अपने जन्मदिन का केक काटा और फिर नाच गाना हुआ। जश्न में 'अनुपमा' का परिवार भी शामिल हुआ और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से जुड़े लगभग सारे किरदारों को देखा गया। इस मौके पर रोहित पुरोहित अपनी पत्नी और नवजात शिशु के साथ पहुंचे। रोहित ने अपने बेबी को सेट पर मौजूद सारे बड़े स्टार्स का आशीर्वाद दिलवाया। सीरियल के 5000 एपिसोड पूरे होने पर 'अनुपमा' की बा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज के समय में 1000 एपिसोड भी पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इतनी लंबी तो शादियां भी नहीं टिकती हैं, जितना लंबा हमारा सीरियल टिक गया है। उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय राजन शाही को जाता है, जिन्होंने सीरियल की इतनी मजबूत नींव रखी है। बस यही कामना है कि जितने आसमान में तारे हों, उतने एपिसोड हमारे हों।

सीरियल में मुख्य भूमिका निभा रहे अरमान और अभीरा ने कहा कि ये पूरी टीम की मेहनत के साथ-साथ दर्शकों का प्यार भी है, जिन्होंने इतने सालों तक सीरियल को पसंद किया और आज 5000 एपिसोड पूरे हो पाए हैं। हमें नहीं लगता है कि अभी तक किसी सीरियल ने इतने एपिसोड पूरे किए हैं, ये हमारे लिए और पूरी टीम के लिए बहुत खुशी का दिन है। वहीं अभीरा ने कहा कि आज ये रिश्ता का पूरा परिवार यहां मौजूद है और शो की पिछली कास्ट भी आई है। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें सब की मेहनत है। बता दें कि ये रिश्ता सीरियल में फिलहाल अक्षरा की चौथी पीढ़ी को दिखाया जा रहा है। सीरियल की स्टोरी अक्षरा और नैतिक की लव स्टोरी से शुरू हुई, जिसके बाद कार्तिक और नायरा आए। फिर शो में अभिमन्यु और अक्षरा की लव स्टोरी दिखाई गई और अब अरमान और अभीरा शो को लीड कर रहे हैं। सीरियल का स्पिन ऑफ शो 'ये रिश्ते हैं प्यार के' भी काफी हिट हुआ था।

यामी गौतम ने फिल्मों के 'पेड प्रमोशन' की आलोचना की

नई दिल्ली/भाषा। अभिनेत्री यामी गौतम ने अपने पति आदित्य धर की फिल्म ''धुरंधर'' के प्रदर्शन से पहले बॉलीवुड में फिल्मों के प्रचार के लिए भारी रकम खर्च करके फिल्म को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति की आलोचना की और कहा कि 'पेड प्रमोशन' का यह चलन फिल्म उद्योग के भविष्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा।

अभिनेत्री ने बृहस्पतिवार को अपने 'एक्स' हैंडल पर एक 'नोट' साझा कर फिल्म के नकारात्मक प्रचार की आलोचना की, जो शुक्रवार को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। उन्होंने लिखा, ''एक बात है जो मैं बहुत समय से कहना चाह रही थी। मुझे लगता है आज वो दिन है और मुझे कहना ही होगा। फिल्म के प्रमोशन के नाम पर पैसे देने का ये तथाकथित चलन, ताकि फिल्म का अच्छा 'प्रचार' हो, वरना 'वे' (फिल्म रिलीज होने से पहले ही) लगातार नकारात्मक बातें लिखते रहेंगे, जब तक आप 'उन्हें' पैसे नहीं देते। ये एक तरह की जबरन वसूली जैसा लगता है।''

गौतम ने कहा, ''सिर्फ इसलिए कि यह व्यवस्था किसी के लिए भी सुलभ है, चाहे वह किसी फिल्म को 'प्रचारित' करने के लिए हो या किसी अन्य अभिनेता/फिल्म के खिलाफ नकारात्मकता फैलाने के लिए, यह एक ऐसी ''महामारी'' है जो हमारे उद्योग के भविष्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगी।''

''उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'', ''बाला'' और ''विक्की डोनर'' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर गौतम ने स्थिति की तुलना दक्षिण सिनेमा उद्योग से की और कहा कि वहां ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि कलाकार एकजुट रहते हैं, इसलिए हिंदी सिनेमा में भी कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है।

निर्माणाधीन सालासर बालाजी मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन

‘चक्रव्यूह’ नामक नाटक के पोस्टर का हुआ विमोचन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर की सालासर बालाजी सेवा समिति के तत्वावधान में पूर्णिमा के अवसर पर गत गुरुवार को बन्नरघट्टा रोड़ स्थित निर्माणाधीन सालासर बालाजी मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन दोपहर 3 बजे से किया गया। कार्यक्रम के लाभार्थी सतीश मित्तल और प्रकाश चौधरी परिवार ने बालाजी महाराज के चित्र के समक्ष विधिवत पूजा कर सुंदरकांड का शुभारंभ किया। इसके उपरांत नारायण बाहेती की टीम द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का संगीतमय वाचन किया गया । सभी उपस्थित भक्तों ने श्रद्धा और आस्था के साथ सुंदरकांड पाठ का लाभ लिया। आयोजकों ने समारोह के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर निर्माण की प्रगति और इसकी संरचना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर लगभग 25 हजार वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित हो रहा है तथा अप्रैल 2028 तक पूर्ण होने की योजना है। इस मंदिर के वास्तुकार चेतन सोमपुरा हैं तथा सम्पूर्ण मंदिर में बंशी पहाड़पुर पत्थर का उपयोग हो रहा है। मंदिर में 3 मुख्य शिखर होंगे तथा मुख्य शिखर की ऊंचाई 72 फीट होगी।

मंदिर में प्रवेश के लिए तीन प्रवेश द्वार होंगे तथा पत्थर के 8 मुख्य स्तंभ होंगे। 7 हजार वर्गफीट के रंगमंडप, 2910 वर्गफीट का बालाजी का गर्भगृह सहित दुर्गामाता व शिव परिवार का गर्भगृह बन रहा है। आयोजकों ने 11 जनवरी को कनकपुरा रोड स्थित प्रेस्टीज ऑडिटोरियम में प्रस्तावित चक्रव्यूह’ नाटक की जानकारी दी। अतुल कौशिक द्वारा निर्देशित इस चक्रव्यूह’ नाटक में महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर चक्रव्यूह कार्यक्रम का पोस्टर का विमोचन समिति के उपाध्यक्ष सतीश मित्तल, सचिव मनित सोमानी, मंदिर समिति के ट्रस्टी, सदस्य, बोर्ड के सदस्य, विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी व सहयोगियों द्वारा किया गया। इस सुन्दरकांड के कार्यक्रम में समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रत्येक पूर्णिमा पर निर्माणाधीन मंदिर परिसर में सुंदरकांड और अमृत भोग का नियमित आयोजन जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में बालाजी महाराज को अमृत भोग अर्पित किया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

डागुआ ड्रग एंड एल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ उद्घाटन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वेल्लूर। गुडियातम के गोपालपुरम स्थित एक निजी सभा भवन में शुक्रवार को डागुआ ड्रग एंड एल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर वेलफेयर एसोसिएशन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अशोक कुमार रामसामी ने फीता काटकर एसोसिएशन का शुभारंभ किया।

इसके बाद एसोसिएशन की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई कार्यकारिणी के गठन पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश सचिव कुकन की अगुवाई में डॉ. पुरोषतमण को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। वहीं शक्तिवेल को सचिव, नरेश को संयोजक, कई अन्य पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया।

समारोह में विशेष अतिथि दिंडीकल मधुसूदन, प्रदेश उपसचिव राजेंद्रन सहित अनेक सदस्य मौजूद थे। अशोक कुमार रामसामी एवं कुकन ने नव–निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाणपत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

हड़ताल

असम की 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के कर्मचारी नौकरी रेगुलर करने, सही वेतन, लंबे समय से रुके हुए ओवरटाइम के पेमेंट वगैरह की मांग को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान।

विजयन ने जमात-ए-इस्लामी और हिंदूवादी संगठनों की सोच एक जैसी बताई

कोच्चि। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को कहा कि जमात–ए–इस्लामी और हिंदूवादी संगठनों की सोच एक जैसी है और उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी लाभ के लिए मुस्लिम संगठन के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया तथा उनके गठबंधन को आत्मघाती करार दिया। शुक्रवार को एर्नाकुलम प्रेस क्लब में मीट द प्रेस’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जमात–ए–इस्लामी केरल में कई मामलों में हस्तक्षेप करता है जबकि यह राज्य में संचालित होने वाला पारंपरिक संगठन नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि केरल के मुस्लिम समुदाय में सुन्नी, मुजाहिद और अन्य अल्पसंख्यक शामिल हैं और उनमें से अधिकांश जमात–ए–इस्लामी को मान्यता नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी के इस कदम को आत्मघाती रुख बताते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के मतदाता जमात–ए–इस्लामी की विचारधारा और राजनीति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ वोटों के लिए एक अपवित्र गठबंधन बनाया है। विजयन ने अबुल आला मौदूदी की शिक्षाओं का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि जमात–ए–इस्लामी ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन पैदा किया है। उन्होंने कहा, भारत में राजनीतिक इस्लामवादी और हिंदुत्व विचारकों की एक जैसी सोच है। भले ही वे एक–दूसरे का विरोध करते दिखें लेकिन उन्होंने सहयोग की संभावना तलाश ली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2011 में जमात ए इस्लामी द्वारा स्थापित राजनीतिक शाखा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया’ की शुरूआत के दौरान उसके कार्यक्रम में संगठन से बाहर का इकलौता व्यक्ति भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता डॉ. जे. के. जैन थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस संगठन ने 2023 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से बातचीत की थी। अन्य मुद्दों पर उन्होंने कहा कि केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है और पिछले साढ़े नौ वर्षों में इस पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।

कर्म बांधते समय सचेत रहें, गलती होने पर पश्चाताप के भाव रखें : नरेश मुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु । श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अलसूर के तत्वावधान में महावीर भवन में आयोजित प्रवचन में नरेश मुनिजी ने कहा कि यह संसार वर्तुलाकार है। न इसका आदि है और न अंत है। अनादि काल से संसार है और अनादि काल तक रहेगा। जीव के कर्म ही संसार को चलाते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म चक्र से संसार चक्र का अंत कर सकते हैं। संसार चक्र का अंत होते ही सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धत्व के लिए हमारे पुरुषार्थ में ललक होनी चाहिए। मात्र कल्पना से सिद्धि नहीं होती है। हम कर्म बांधते समय सचेत रहें और गलती महसूस होने पर पश्चाताप के भाव रखें। पाप करके प्रमोद करने से भयंकर कर्म बंध होते हैं।प्रवचन प्रारंभ करते हुए साध्वी सुप्रभाजी ने कहा कि श्रावक को जिनवाणी रुचि के साथ सुननी चाहिए। पुण्य से जिनवाणी का संयोग मिलता है। जिनवाणी श्रवण से पुण्य बंध होता है और संसार में पुण्य जरूरी होता है।शालीभद्र मुनिजी ने कहा कि जीवन में शांति चाहिए तो हम न तो किसी से कोई अपेक्षा रखें, न आवेश में आएं और न कभी हताश हों। अपेक्षा दुख देती है। आवेश क्षणिक होता है, लेकिन परिणाम भयंकर होते हैं। हताश हो जाने से प्रगति का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। अलसूर संघ के मंत्री अभय कुमार बांठिया ने सभा का संचालन किया। अध्यक्ष धनपत राज बोहरा ने अतिथियों का स्वागत किया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अणम्मा देवी उत्सव

भगत सिंह युव गर्जने संघ कुरूबरहल्ली द्वारा आयोजित अणम्मा देवी उत्सव में मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की। अन्नदान कार्यक्रम में सेवा भी की। आयोजकों ने मुणोत को सम्मानित किया।

जैन समाज राजनीति में भी सक्रिय हो: सईद अहमद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एवं डी. देवराज अर्स ट्रक टर्मिनल्स के चेयरमैन सईद अहमद से जैन समाज के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अहमद ने कहा कि समाज सेवा एवं जीव दया में हमेशा अग्रणी रहने वाला जैन समाज राजनीति में उतना सक्रिय नहीं है।उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों में जैन समाज ने पूरी दुनिया में परचम लहराया है और अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, लेकिन राजनीति में समाज का प्रतिनिधित्व नगण्य है।

साथ ही, उन्होंने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि अगर जैन समाज राजनीति में सक्रिय होता है तो अपनी सोच एवं विचारों से जनता के लिए नए आयाम लिख सकता है। समाज को इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

प्रतिनिधि मंडल में शामिल कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ बोहरा ने अहमद से कहा कि निःसंदेह जैन समाज अपनी व्यापारिक गतिविधियों पर ही ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन अब समय की मांग के अनुसार राजनीति में कदम बढ़ाएगा।

उन्होंने इस क्षेत्र में सहयोग का अनुरोध किया। श्रीरामपुरम श्रीसंघ के अध्यक्ष ताराचंद जैन ने सईद अहमद से अनुरोध किया कि जैन समाज के राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ताओं को सरकारी निगम मंडलों में उचित स्थान दिलाएं, ताकि राजनीतिक रूप से उनके साथ न्याय हो सके।ङ्कङ्कगुजराती समाज के अमीन ने अहमद से अनुरोध किया कि वे जैन समाज को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने में गंभीरता से प्रयास करें्। सईद अहमद ने हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया।

यूपीआई को मंजूरी के लिए आठ अन्य देशों के साथ बातचीत जारी: वित्तीय सेवा सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त सेवा सचिव एम. नागराजू ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने डिजिटल भुगतान मंच यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाने के लिए आठ देशों के साथ बातचीत कर रहा है। फिलहाल भारत की लोकप्रिय भुगतान प्रणाली यूपीआई को आठ देशों में स्वीकार्य किया गया है। इनमें भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरीशस, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), श्रीलंका और फ्रांस शामिल हैं। इससे भारतीय पर्यटक विदेशों में लेन–देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नागराजू ने यहां एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम अब यूपीआई लेनदेन को संभव बनाने के लिए करीब सात–आठ देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनमें पूर्वी एशिया के कई देश शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारत कुछ देशों के साथ व्यापार वार्ताओं के दौरान यूपीआई को भी शामिल कर रहा है।

नागराजू ने कहा, कुछ देशों के साथ जिन व्यापार वार्ताओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें यूपीआई का भी एक पहलू रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में गहराई से शामिल वित्तीय–प्रौद्योगिकी उद्योग भी इसमें अपनी भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि भारत को लागत और पैमाने के स्तर पर बढ़त हासिल है और इस लाभ का उपयोग देश के हित में करना चाहता है।

‘दूसरों के लिए कांटे उगाने पर हमें फूल की प्राप्ति नहीं हो सकती’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

होसुर। साध्वी भव्यगुणाजी ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साहस ही जीवन की विशेषताओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। मनुष्य में सभी गुण हों, वह विद्वान, शक्तिशाली, धनवान, सद्गुण संपन्न हो, लेकिन उसमें साहस न हो तो वह अपनी विशेषताओं, योग्यताओं का कोई उपयोग नहीं कर सकता है। साध्वी शीतलगुणाजी ने कहा कि जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति भगवान के चरणों में ही होती है। इसके लिए वैर–विरोध का त्याग कर जीवन को अच्छा बनाना होता है। हम दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों की तरफ देखें ओर उन दोषों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हम सच्चे सुख की प्राप्ति की कामना तो करते हैं, लेकिन भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगाते हैं।

जब तक राग–द्वेष में उलझे रहेंगे, सच्चे सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम संवाद रखेंगे तो मतभेद भी समाप्त होंगे, एक–दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान के भाव भी जाग्रत होंगे। कई बार हमारे बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। हम एक–दूसरे की विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं। आपसी संवाद नहीं होने पर ये मतभेद गहरे हो जाते हैं। कई बार तो संवादहीनता के कारण मनभेद की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचें। दूसरों के लिए कांटे उगाने पर हमें फूल की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरों के दोष देखना मानव की कमजोरी है। व्यक्ति दूसरे इन्सान में तो क्या भगवान में भी दोष ढूंढ़ लेता है।

उन्होंने कहा कि व्यक्ति जितना समय दूसरों के दोष देखने ओर निंदा करने में लगाता है, यदि उतना समय स्वयं को देखने ओर स्वनिंदा में लगा ले तो उसके जीवन का कल्याण हो जाए। बाहरी आंखें बंद होने से पहले भीतर की आंखें खुल जाएं तो जीवन का कल्याण हो जाता है। पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण विहार के दौरान सुरक्षा प्रदान की। साध्वीवृंद ने मांगलिक श्रवण करवाकर सभी का आभार व्यक्त किया।

सुसवाणी माता मंदिर और अतिबलेश्वर महादेव मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के होसूर रोड स्थित सुसवाणी माता धाम की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। धाम स्थित सुसवाणी माता मंदिर की नौवीं वर्षगांठ एवं अतिबलेश्वर महादेव मंदिर की छठी वर्षगांठ पर धाम निर्माता एवं संचालक भंवरीबाई घेवरचंद सुराणा परिवार के भंवरीबाई, दिलीप–डॉ. अर्चना, मोनिका, निश्रा, जयंतीलाल, शैलेष सिरोया आदि ने दोनों मंदिर शिखरों पर नूतन ध्वजा चढ़ाई।

इससे पहले, धाम प्रतिष्ठित पांचों माताजी की रजत प्रतिमाओं का अभिषेक तथा महादेवजी एवं माताजी वंदित हवन पंडित वीरेंद्र पांडेय एवं सुधीर पांडेय के मंत्रोच्चार के बीच किया गया। ध्वजारोहण के बाद जयकारे के साथ माताजी को छप्पन भोग भी अर्पित किया गया।

इस अवसर पर पूर्व विधायक निर्मल कुमार सुराणा, मोरखाणा मुख्यधाम के महामंत्री नरेंद्र सुराणा दिल्ली, सुराणा संघ अध्यक्ष महिपाल सुराणा, पूर्व अध्यक्ष रिखबचंद, सरदारमल, राजेंद्र कुमार, कार्यकारिणी सदस्य कन्हैयालाल, नरेंद्र, सोहनलाल, देवराज, किशोर सुराणा, संजय, भावेश सोनीगरा, पीयूष जैन, विजय भाई शाह सहित सुराणा संघ, सुसवाणी माता भक्त मंडल एवं सुसवाणी माता महिला मंडल के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। महिला मंडल ने संगीतमय भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी।

भारत-ईएईयू तरजीही व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर के पक्ष में रूसी राष्ट्रपति

नई दिल्ली/भाषा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि भारत एवं यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच तरजीही व्यापार समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर होने से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह में बाधाएं कम करने में मदद मिलेगी।

भारत और ईएईयू ने पिछले सप्ताह इस मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर पहले दौर की बातचीत की थी।

ईएईयू के पांच सदस्य देशों–रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एवं किर्गिजस्तान के साथ भारत ने 20 अगस्त को समझौते के लिए नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिया था। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए पुतिन ने यहां भारत–रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के कारोबारी समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार का आकार लगभग 70 अरब डॉलर है। पुतिन ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह के लिए बाधाएं कम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच प्राथमिक व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर से एक मजबूत प्रोत्साहन दिया जा सकता है। पुतिन ने कहा कि रूसी प्रतिनिधिमंडल केवल ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा करने नहीं बल्कि तेल और गैस आपूर्ति के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी यहां है। उन्होंने कहा कि रूसी कंपनियां भारत से उत्पादों और सेवाओं की खरीद में कई गुना वृद्धि करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि मजबूत द्विपक्षीय निपटान और भरोसेमंद भुगतान एवं बीमा व्यवस्था के बगैर मुक्त व्यापार के बारे में सोचना भी असंभव है।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**